



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 262]	नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 26, 2019/भाद्र 4, 1941
No. 262]	NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 26, 2019/BHADRA 4, 1941

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

अधिसूचना

(द्विपक्षीय रक्षोपाय जांच)

नई दिल्ली, 26 अगस्त, 2019

[मामला सं.: (एस जी) 04/2019]

विषय : भारत – मलेशिया व्यापक आर्थिक सहयोग करार (द्विपक्षीय रक्षोपाय कदम) नियमावली 2017 के अंतर्गत मलेशिया से भारत में “परिष्कृत प्रक्षालित गंध रहित पामोलिन एवं परिष्कृत प्रक्षालित गंध रहित पाम ऑयल” के आयातों के संबंध में द्विपक्षीय रक्षोपाय जांच का प्रारंभिक जांच परिणाम।

फा. सं. 22/4/2019—डी जी टी आर.—भारत की जनतांत्रिक सरकार और मलेशिया की सरकार (सी ई सी ए) के बीच व्यापक आर्थिक सहयोग करार के अनुच्छेद 5 और उसकी (द्विपक्षीय रक्षोपाय कदम) भारत मलेशिया व्यापक आर्थिक सहयोग करार नियमावली 2017 के संबंध में।

क. प्रक्रिया

जबकि, भारतीय घरेलू उत्पादकों की ओर से मैसर्स टी पी एम कंसल्टेंट, नई दिल्ली के माध्यम से सॉल्वेट एक्सट्रेक्टर एसो. ऑफ इण्डिया के द्वारा भारत मलेशिया आर्थिक व्यापक आर्थिक सहयोग करार, (द्विपक्षीय रक्षोपाय कदम) रक्षोपाय कदम (नियमावली 2017) (जिसे आगे उक्त नियमावली अथवा “द्विपक्षीय रक्षोपाय नियमावली” के रूप में भी कहा जाता है) के अंतर्गत यह आरोप लगाते हुए एक आवेदन दायर किया गया है कि “परिष्कृत प्रक्षालित गंध रहित पामोलिन ‘परिष्कृत प्रक्षालित गंध रहित पाम ऑयल’ (इसके बाद “विचाराधीन उत्पाद” अथवा “पी यू सी” अथवा संबद्ध वस्तुओं के रूप में भी

कहा जाता है) का बढ़ा हुआ आयात मलेशिया (संबद्ध देश के रूप में भी कहा जाता है) से हुआ है जिसके कारण भारत में समान अथवा प्रत्यक्ष तौर पर प्रतिस्पर्धी उत्पाद के घरेलू उत्पादकों को गंभीर क्षति हुई है और गंभीर क्षति होने का खतरा है।

1. इसके बारे में संतुष्ट होने पर की द्विपक्षीय रक्षोपाय नियमावली के अनुच्छेद 4 की आवश्यकताओं को पूरा किया गया था, मलेशिया से "परिष्कृत प्रक्षालित गंध रहित पामोलिव परिष्कृत प्रक्षालित गंध रहित पाम ऑयल" के बढ़े हुए आयातों की द्विपक्षीय रक्षोपाय जांच की शुरुआत भारत के राजपत्र असाधारण में प्रकाशित दिनांक 14 अगस्त, 2019 की जांच शुरुआत की सूचना के द्वारा किया गया था।
2. घरेलू उद्योग द्वारा दायर किये गये आवेदन के अगोपनीय पाठ की प्रति के साथ दिनांक 14 अगस्त, 2019 की जांच शुरुआत की सूचना की एक प्रति केंद्र सरकार को वाणिज्यिक मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, अन्य प्रशासनिक मंत्रालयों, भारत में इसके उच्च आयोग के माध्यम से मलेशिया की सरकार और आवेदन में यथाउल्लिखित अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उक्त नियमावली के नियम 5 (2) और 5 (3) के अनुसार अग्रेसित की गई थी।
3. प्रश्नावली मलेशिया में यह उत्पाद निम्नलिखित विदेशी उत्पादकों को भेजा गया था :
 - i. फेल्डा मार्केटिंग सर्विसिस सन बीएचडी
 - ii. गोल्डन जोमालिना फूड इंडस्ट्री सन बीएचडी
 - iii. 101 इडिब्ले ऑयल सन बीएचडी
 - iv. केआई-केपोंग इडिब्ले ऑयल सन बीएचडी
 - v. मेवहोलियो इंडस्ट्रीज सन बीएचडी
 - vi. नगो चेव हाँग ऑयल्स एंड फ्लेट्स (एम) सन
 - vii. साउदर्न इडिब्ले ऑयल इंडस्ट्री (एम) सन
 - viii. क्वांटस ऑयल सन बीएचडी
 - ix. सारवक ऑयल पाम बेहर्ड
 - x. सियम डर्बी ऑयल्स लंगत रिफाइनरी
 - xi. गोल्डन एग्री रिसॉसिस लिमि.
 - xii. विलमर इंटरनेशनल
4. हितबद्ध पक्षकारों से यह अनुरोध किया गया था कि ये जांच की शुरुआत की संबंधित सूचना के 30 दिनों के भीतर लिखित रूप में अपने विचार से अवगत करायें।
5. याचिकाकर्ताओं ने अपने आवेदन में नीचे दिये गये अनुसार अनुरोध किया है :
 - क. इस करार के अंतर्गत रक्षोपाय कदमों के लिए आवेदन सोल्वेंट एक्ट्रे एसो. ऑफ इण्डिया के द्वारा कार्य किया गया है और इस कारण से यह माना जाना चाहिए कि यह आवेदन भारत में "परिष्कृत प्रक्षालित गंध रहित पामोलिव परिष्कृत प्रक्षालित गंध रहित पाम ऑयल" के उत्पादकों की ओर से दायर किया गया है।
 - ख. जांच के अधीन यह उत्पाद "परिष्कृत प्रक्षालित गंध रहित पामोलिव परिष्कृत प्रक्षालित गंध रहित पाम ऑयल" (क्रमशः आर बी डी पाम ऑयल और आर बी डी पामोलिव के रूप में भी जाना जाता है) है, जो एच एस को 15119010 और 15119020 के अंतर्गत आता है।
 - ग. विचाराधीन उत्पाद का आमतौर पर अस्वास्थ्यकर वसा जैसे नकली मक्खन, लघुकरण और वनस्पति घी तैयार करने के लिए किया जाता है।
 - घ. ऐसे अनेक उत्पादक हैं जो इस एसोसिएशन के सदस्य हैं और उनमें से नौ सदस्यों ने इस याचिका का समर्थन किया है।
 - ङ. वर्तमान आवेदन घरेलू उत्पादकों के एक संघ द्वारा किया गया है, इसे माना जाना चाहिए कि यह आवेदन घरेलू उत्पादकों की ओर से दायर किया गया है।

- च. यह एसोसिएशन अलग अलग उत्पादक के आंकड़ों को जैसे उत्पादन, बिक्री, भंडार, लाभ आदि इस तथ्य को देखते हुए नहीं रखता है कि यह व्यापारिक रूप से संवेदनशील आंकड़े हैं और यह एसोसिएशन इस देश में प्रतिस्पर्धा कानूनों को देखते हुए यह कार्यकलाप करने के लिए बाध्य नहीं है।
- छ. घरेलू उत्पादन के संबंध में सूचना दो स्रोतों (क) घरेलू कच्चा पाम ऑयल (सी पी ओ) उत्पादन (ख) आयात किये गये कच्चा पाम ऑयल से लिया गया है।
- ज. याचिकाकर्ता यह मानते हुए कि एक मी. ट. तक का माल (सी पी ओ) 0.95 मी. ट. परिष्कृत पाम ऑयल का उत्पादन करता है, कच्चे पाम ऑयल से संबंध वस्तुओं तक परिवर्तन गुणक को लागू कर सकल भारतीय उत्पादन प्राप्त किया है।
- झ. पाम ऑयल कमरे के तापक्रम पर सेमी-सॉलिड (20 डिग्री से.) है। तरल भाग को भौतिक रूप से विभाजन के द्वारा पाम ऑयल के ठोस भाग से अलग किया जा सकता है। विभाजन के बाद तरल भाग को "पाम ओलिन" कहा जाता है जिसे आमतौर पर बोतल में बंद किया जाता है और कूकिंग ऑयल के रूप में बेचा जाता है। ठोस वसा के भाग को "पाम स्टेयरिन" कहा जाता है जो विचाराधीन उत्पाद के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है।
- ञ. संबद्ध वस्तुओं पर लागू मानक दर 100 प्रतिशत है। हालांकि, लागू दर अधिमान्य प्रशुल्क करारों (मलेशिया के साथ सी ई सी ए) और (ए आई एफ टी ए) के अंतर्गत अधिमान्य सीमा शुल्क जिसे दिनांक 31.12.2018 की अधिसूचना संख्या 82/2018 और 84/2018 के अंतर्गत अधिसूचित किया गया था, के कारण कम है। सीमा शुल्क की लागू की गई दर ए आई एफ टी ए और सी ई सी ए करार के लिए उपलब्ध कराई गई दरों के स्तर से काफी कम रही है और सी पी ओ एवं संबद्ध वस्तुओं के लिए सीमा शुल्क के बीच अंतर शतप्रतिशत था। लागू की गई दरों में मार्च 2018 में बहुत अधिक वृद्धि हुई। इसके बाद ही ऐसा हुआ कि सी ई सी ए और आशियान के अंतर्गत लागू सीमा दरें संगत हो गईं।
- ट. याचिकाकर्ता ने मलेशिया और भारत सरकार के बीच किये गये व्यापक आर्थिक सहयोग करार के अनुसरण में इस आवेदन को दायर किया है।
- ठ. मलेशिया की सी ई सी ए करार के अनुसरण में, मलेशिया से कच्चे पाम ऑयल (संबद्ध वस्तुओं का कच्चा माल) के आयातों पर शुल्क को 40 प्रतिशत तक कम किया गया है जबकि संबद्ध वस्तुओं पर शुल्क दिनांक 31.12.2018 के अधिसूचना सं. 82/2018 के माध्यम से 45 प्रतिशत तक कम किया गया है। इस प्रकार से कच्चे माल ऑयल और संबद्ध वस्तुओं पर शुल्क के बीच अंतर केवल 5 प्रतिशत है।
- ड. कच्चे पाम ऑयल और संबद्ध वस्तुओं पर शुल्क के बीच अंतर हमेशा 10 प्रतिशत रहा है। कच्चे पाम ऑयल और संबद्ध वस्तुओं के बीच 10 प्रतिशत से 5 प्रतिशत तक शुल्क के अंतर में कमी के बाद संबद्ध वस्तुओं के मलेशिया से आयातों में बहुत अधिक वृद्धि हुई है।
- ढ. जांच की अवधि में आयात की मात्राओं में बहुत अधिक वृद्धि हुई है। आयातों में 2015-16 से जांच की अवधि तक 516 प्रतिशत तक वृद्धि हुई है। भारत में संबद्ध उत्पाद के आयातों में स्वतंत्र रूप में तथा उत्पादन, खपत और आयातों में हिस्से की तुलना में बहुत अधिक वृद्धि हुई।
- ण. उत्पाद और खपत की तुलना में आयातों में भी बहुत अधिक वृद्धि हुई है। 2015-16 में भारतीय उत्पादन में हिस्से का 8 प्रतिशत आयात हुआ था जो जांच की अवधि में 73 प्रतिशत तक बढ़ गया। इसी प्रकार से 2015-16 में भारतीय खपत में हिस्से का 5 प्रतिशत आयात हुआ जो बढ़कर जांच की अवधि में 32 प्रतिशत हो गया।
- त. मलेशिया से आयात 2015-16 में कुल भारतीय आयातों का केवल 17 प्रतिशत था जो बढ़कर प्रस्तावित जांच की अवधि में कुल आयातों का 78 प्रतिशत हो गया।
- थ. भारत में आयात व्यापक तौर पर इण्डोनेशिया और मलेशिया से हुए हैं। लेकिन मलेशिया के पास भारत – मलेशिया सी ई सी ए करार के अंतर्गत आर वी डी पामोलिव के लिए शुल्क लाभ है और इस कारण से इस देश में अब मलेशिया से संबद्ध वस्तुओं की भारी मात्रा में आवक हो रही है।
- द. घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादन किये जा रहे समान उत्पाद वही है जो आयात किया गया उत्पाद अर्थात् "परिष्कृत प्रक्षालित गंध रहित पामोलिव परिष्कृत प्रक्षालित गंध रहित पाम ऑयल" है। घरेलू उत्पाद की तुलना आयात किये गये उत्पाद से की जा सकती है।

- ध. इस उद्योग को उत्पादन की क्षमताओं का पूर्ण रूप से कम उपयोग के कारण हानि हो रही है। घरेलू उत्पादकों की कठिनाइयों को बढ़ाने के लिए, आयातों में अचानक वृद्धि के कारण भारत में घरेलू उत्पादकों की क्षमता के उपयोग पर आगे और प्रभाव पड़ रहा है।
- न. याचिकाकर्ता ने यह अनुरोध किया है कि चूंकि इस उत्पाद को भंडार में बहुत अधिक समय तक नहीं रखा जा सकता है फिर भी इन्होंने बिक्री के रूप में उत्पादन पर विचार किया है।
- प. भारतीय उद्योग के उत्पादन और बिक्री में बहुत अधिक गिरावट आई है। जबकि इस उत्पाद की मांग में 8,095,565 मी. ट. (2015-16) से कम होकर 7,982,537 मी. ट. (जांच की अवधि की वार्षिकीकृत) हो गई है, घरेलू उद्योग का उत्पादन और उसके परिणामस्वरूप बिक्री 5,558,240 मी. ट. (2015-16) से कम होकर 4,833,716 मी. ट. (जांच की अवधि) हो गई है। इस प्रकार से घरेलू उद्योग के उत्पादन में 7.25 लाख मी. ट. तक गिरावट आई जिसका मूल्य लगभग 3,000 करोड़ रुपए हैं जबकि इस उत्पाद की मांग में केवल 1.13 लाख मी. ट. गिरावट आई।
- फ. इस उद्योग की क्षमता के उपयोग में बहुत अधिक गिरावट आई है। भारतीय उद्योग अपनी क्षमताओं का आधा भी उपयोग नहीं कर रहा है और तब क्षमता के उपयोग में 2009-10 की पहली तिमाही में केवल 31 प्रतिशत तक कमी आई।
- ब. उत्पादन और क्षमता के उपयोग में गिरावट कच्चे पाम ऑयल के आयातों में गिरावट से भी स्पष्ट है। सी पी ओ के आयातों में इस अवधि के दौरान तेजी से गिरावट आई।
- भ. भारतीय उद्योग के बाजार हिस्से में गिरावट आई है जबकि इन आयातों के बाजार हिस्से में बिक्री हुई है। जबकि भारतीय उत्पादकों के पास पूर्व में 69 प्रतिशत बाजार हिस्सा (2015-16) था, लेकिन उसमें 61 प्रतिशत तक (अप्रैल – जून, 2019) तक गिरावट आई है।
- म. संबद्ध आयातों में घरेलू उद्योग की कीमतों में बहुत अधिक कटौती हो रही है। इस प्रकार से यदि भारतीय उत्पादक सी पी ओ का आयात करते हैं, उसे आर बी डी ऑयल में प्रसाधिक करते हैं और बाजार में आर बी डी ऑयल की बिक्री करते हैं तब वे प्रसंस्करण लागतों को भी वसूलने में सक्षम नहीं हो पायेंगे और इसके कारण उन्हें बहुत अधिक वित्तीय हानि होगी।
- य. घरेलू उद्योग के लाभों में इस अवधि के दौरान लगभग 7.6 लाख मी. ट. की बिक्री की हानि और 2500 पीएमटी का उचित न्यूनतम लाभ जो कोई प्रसंस्करणकर्ता, कमाता है पर विचार करते हुए इस अवधि, अप्रैल – दिसंबर, 2018 की तुलना में जनवरी – जून, 2019 में लगभग 268 करोड़ रुपए तक कम हो गया है। इस उद्योग के लाभों में दिसंबर, 2018 तक वृद्धि हो रही थी।
- र. भारतीय उद्योग अपनी क्षमताओं के एक तिमाही कम पर अपने संयंत्र को चला रहा है। जबकि इस देश में आर बी डी की खपत 80 लाख मी. ट. तक है, फिर भी इस देश में 130 लाख मी. ट. तक की क्षमताएं हैं। इस प्रकार से आर बी डी ऑयल का आयात पूर्ण रूप से आवश्यक नहीं है।
- ल. विचाराधीन उत्पाद के प्रसंस्करण में लगाये गये मानव घंटों की संख्या वर्तमान अवधि में कम हो गई है। 20 लाख तक उत्पादन की वार्षिक हानि पर विचार करते हुए, इस उत्पाद के लिए लगाये गये रोजगार में लगभग 3,000 तक कमी आई है।
- व. भारतीय उद्योग की उत्पादकता में जांच की अवधि में बहुत अधिक गिरावट हुई है।
- श. पहले ही हुई गंभीर क्षति के अलावा आयातों के कारण गंभीर क्षति का खतरा उत्पन्न हो रहा है जो निम्नलिखित से सिद्ध होता है :
- आयातों की मात्रा में अपेक्षाकृत कम अवधि में बहुत अधिक वृद्धि हुई है।
 - घरेलू बाजार में एक बहुत बड़ा हिस्सा पहले से ही आयातों के कब्जे में है और इस प्रकार के हिस्से में वृद्धि हो रही है।
 - घरेलू कीमत और आयात किये गये उत्पाद के बीच अंतर बहुत अधिक है जो प्रसंस्करण लागत और खर्चों के लिए उचित समायोजन किये जाने के बाद सी पी ओ और आर बी डी पामोलिन की आयात कीमत के द्वारा सिद्ध होता है।

- iv. मलेशिया का बहुत बड़ा उत्पादन आधार है और इसका निर्यात बहुत अधिक मात्रा में होता है। यह तथ्य कि आयातों में इतनी तेजी से वृद्धि हुई है। अपने आप में संभावित क्षति को स्पष्ट रूप से दर्शाता है जो घरेलू प्रसंस्करणकर्ताओं को हो सकता है।
- प. ऐसा कोई अन्य कारक नहीं है जिसे बढ़े हुए आयातों को छोड़कर घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति का कारण माना जा सकता है।
- स. आयातों की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री कीमतों की तुलना में पर्याप्त रूप से कम है।
- ह. घरेलू उद्योग बिक्री अवसरों तथा सामान्य मार्जिन की हानि उठा रहा है। इसके परिणामस्वरूप बिक्री, लाभ, निवेश पर लाभ और नकद प्रवाह कम कीमत के आयातों के लगातार होने के कारण कम हो रहा है।
- क्ष. बढ़े हुए आयातों के फलस्वरूप आयातों के बाजार हिस्से में वृद्धि और घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में कमी हुई है।
- त्र. याचिकाकर्ता ने भारत – मलेशिया व्यापक आर्थिक सहयोग करार (द्विपक्षीय रक्षोपाय कदम) नियमावली, 2017 के अंतर्गत किये गये प्रावधान के अनुसार रक्षोपाय कदम का अनुरोध किया है। कच्चे ऑयल की आयात कीमत, शामिल प्रसंस्करण लागत और उचित लाभ (5 प्रतिशत) और आयातों की पहुंच कीमत पर विचार करते हुए लक्ष्य कीमत के बीच कीमत में अंतर लगभग 18 प्रतिशत है।
- ज. रक्षोपाय कदम की मांग करने का उद्देश्य घरेलू उद्योग को इसकी क्षमता के उपयोग में सुधार लाने में समर्थ बनाने के लिए है, जिससे की घरेलू उद्योग जिंदा रह सके।
- कक. याचिकाकर्ता ने एक वक्त के लिए रक्षोपाय उपायों का अनुरोध किया है। याचिकाकर्ता ने अनंतिम रक्षोपाय उपायों को लगाये जाने के लिए भी अनुरोध किया है। यह अनुरोध किया गया था कि अंतरिम उपाय विचाराधीन उत्पाद के बढ़े हुए आयातों के परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग के कार्य निष्पादन में तेजी से गिरावट को देखते हुए आवश्यक है।
- खख. यह भी अनुरोध किया गया था कि मलेशिया से आयातों में बहुत अधिक वृद्धि हुई है जबकि भारतीय उद्योग से उत्पादन, बिक्री और उसके परिणामस्वरूप क्षमता के उपयोग में पर्याप्त रूप से गिरावट आई है।

ख. याचिकाकर्ताओं द्वारा अनंतिम उपायों के लिए किये गये अनुरोधों का विश्लेषण

6. याचिकाकर्ताओं के अनंतिम द्विपक्षीय रक्षोपाय कदमों को लागू करने के लिए अनुरोध की जांच की गई थी। भारत – मलेशिया व्यापक आर्थिक सहयोग करार (द्विपक्षीय रक्षोपाय कदम) नियमावली, 2017 जिसे दिनांक 21.06.2017 को अधिसूचना संख्या 55/2017 – एनटी – सीमा शुल्क के माध्यम से जारी किया गया था, के नियम 8 में यह निर्धारण है कि महानिदेशक जांच तेजी से करने की कार्यवाही कर सकते हैं और नाजुक परिस्थितियों में महानिदेशक बढ़े हुए आयातों, जिसके कारण गंभीर क्षति हो रही है अथवा घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति होने का खतरा है और जहां अनंतिम द्विपक्षीय रक्षोपाय कदम लगाये जाने में विलंब के कारण क्षति होगी जिसे पूरा करना मुश्किल होगा के संबंध में आरंभिक जांच परिणाम रिकार्ड कर सकते हैं। जांचों को शासित करने वाले सिद्धांत भारत – मलेशिया व्यापक आर्थिक सहयोग करार (द्विपक्षीय रक्षोपाय कदम) नियमावली, 2017 के नियम 5 में दिया गया है जो नियम 8 से स्वतंत्र है। नियम 13 में पहले ही लगाये गये और वसूले गये अनंतिम शुल्क की तुलना में जांचों के निष्कर्ष निकाले जाने के बाद लगाए गए रक्षोपाय शुल्क के कम होने की स्थिति में अलग अलग रक्षोपाय शुल्क वापसी का प्रावधान है। इस नियमावली के नियम 5, 8 और 13 के संगत पठन से यह निष्कर्ष निकलता है कि इस नियमावली में आरंभिक जांच परिणामों के आधार पर अनंतिम रक्षोपाय शुल्क और अंतर शुल्क की वापसी की तेजी से सिफारिश किये जाने का प्रावधान है यदि यह पता लगाया जाता है कि प्राकृतिक न्याय का पालन करते हुए जांच के निष्कर्ष के बाद लगाया गया शुल्क जैसा कि नियम 5 में उल्लेख किया गया है, अनंतिम रक्षोपाय शुल्क से कम हो। हालांकि, नाजुक परिस्थितियों में, अनंतिम रक्षोपाय शुल्क लगाये जाने में किसी प्रकार के विलंब से क्षति हो सकती है, जिसे पूरा करना मुश्किल होगा। तदनुसार, इसे दूरदर्शी माना गया था कि इस तथ्य का आकलन करने के लिए परिस्थितियों का विश्लेषण किया जाये कि क्या वह नाजुक परिस्थितियों की श्रेणी में आता है।
7. यह नोट किया जाता है कि संबद्ध आयातों में 2016-17 में 626,362 मी. ट. से जनवरी – मार्च, 2019 में 1,974,337 मी. ट. (वार्षिकीकृत आधार पर) और आगे अप्रैल – जून, 2019 की अवधि में 3,218,112 मी. ट.

(वार्षिकीकृत आधार पर) तक बहुत अधिक वृद्धि हुई है जो भारत में कुल आयातों का 87 प्रतिशत, भारतीय उत्पादन का 112 प्रतिशत और भारतीय खपत का 40 प्रतिशत है। याचिकाकर्ताओं ने दावा किया है कि संबद्ध आयातों में तेजी से वृद्धि के फलस्वरूप घरेलू उत्पादकों और इस उत्पाद के लिए उनके उत्पाद की सुविधाओं के उपयोग पर बहुत अधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। उन्होंने अपनी याचिका में यह भी दावा किया है कि संबद्ध आयातों में बहुत अधिक अचानक वृद्धि और आगे आयातों में वृद्धि के खतरे पर विचार करते हुए, घरेलू उत्पादकों को गंभीर क्षति होना आसन्न है, यदि उक्त नियमावली के अनुसार तत्काल रक्षोपाय शुल्क लागू नहीं किया जाता है। इस कारण से महानिदेशक ने याचिकाकर्ताओं के इस तर्क की जांच की है कि अनंतिम रक्षोपाय शुल्क लगाये जाने की आवश्यकता की नाजुक स्थिति यदि मौजूद है और अनंतिम उपायों को लागू करने में किसी प्रकार के विलंब से क्षति होगी, जिसे पूरा करना कठिन होगा।

8. उक्त नियमावली और करार के विभिन्न प्रावधानों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने से यह दृष्टिगत होता है कि इस नियमावली में हितवद्ध पक्षकारों से प्रश्नावली का उत्तर और अन्य सूचना की प्रतीक्षा किये गये बिना उपयुक्त मामलों में अंतरिम उपायों को रिकार्ड करने पर विचार किया जाता है। इस कारण से जांच की शुरुआत की सूचना के प्रतिउत्तरों की प्रतीक्षा किये बिना द्विपक्षीय रक्षोपाय कदम लागू किये जाने के लिए अनुरोध की जांच करना उपयुक्त होगा। हालांकि, महानिदेशक जांच की सभी पहलुओं पर जांच की प्रक्रिया के दौरान किसी हितवद्ध पक्षकार द्वारा दिये गये किसी सूचना/ साक्ष्य अथवा औचित्य पर विचार करेंगे।

ग. याचिका की जांच

9. याचिकाकर्ता द्वारा दायर किये गये आवेदन की जांच रक्षोपाय शुल्क तत्काल लगाये जाने के लिए की गई है। तदनुसार याचिकाकर्ता द्वारा अपनी याचिका में उपलब्ध कराई गई सूचना पर प्रारंभिक निर्धारण के उद्देश्य से महानिदेशक द्वारा विचार किया गया है। हालांकि, महानिदेशक सभी हितवद्ध पक्षकारों से सूचना और विचार प्राप्त होने के बाद अपने अंतिम निर्धारण को रिकार्ड करेंगे।

I. विचाराधीन उत्पाद (पी यू सी)

10. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद "परिष्कृत प्रक्षालित गंध रहित पामोलिव परिष्कृत प्रक्षालित गंध रहित पाम ऑयल" (क्रमशः आर बी डी पाम ऑयल और आर बी डी पामोलिन के रूप में भी जाना जाता है) है, जो सीमा प्रशुल्क अधिनियम के एच एस कोड 15119010 और 15119020 के अंतर्गत के आता है। आर बी डी पामालिन परिष्कृत प्रक्षालित और गंध रहित प्रकार का पाम ऑयल है जिसे पाम के फल की तराई करने के बाद निकाला जाता है। विचाराधीन उत्पाद का आमतौर पर उपयोग अस्वास्थ्य कर वसाओं जैसे नकली मक्खन, लघुकरण और वनस्पति घी का निर्माण करने के लिए किया जाता है।

II. घरेलू उद्योग

11. भारत – मलेशिया व्यापक आर्थिक सहयोग करार (द्विपक्षीय रक्षोपाय कदम) नियमावली, 2017 के नियम 2(ख) में नीचे दिये गये अनुसार प्रावधान है :
"घरेलू उद्योग" का आशय भारत में समान वस्तु अथवा प्रत्यक्ष रूप प्रतिस्पर्धी वस्तु के समग्र के रूप में आयात किये गये वस्तुओं, उत्पादकों के संबंध में है; अथवा
12. इसके अलावा, आवेदन प्रस्तुत करने के संबंध में नियम 4 में नीचे दिये गये अनुसार प्रावधान है :
महानिदेशक समान वस्तु अथवा प्रत्यक्ष तौर पर प्रतिस्पर्धी वस्तु घरेलू उत्पादकों की ओर से अथवा उनके द्वारा लिखित आवेदन के प्राप्त होने पर व्यापार करार के अंतर्गत सीमा शुल्क में कमी अथवा उसकी समाप्ति के फलस्वरूप मूल वस्तु के बड़े हुए आयातों के कारण घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति के होने अथवा हुई क्षति गंभीर क्षति के खतरे का निर्धारण करने के लिए जांच शुरू कर सकते हैं।
13. यह आवेदन भारत में "परिष्कृत प्रक्षालित गंध रहित पामोलिव परिष्कृत प्रक्षालित गंध रहित पाम ऑयल" के घरेलू उत्पादकों की ओर से साल्वेंट एक्ट्रेचर एसोसिएशन ऑफ इण्डिया के द्वारा दायर किया गया है। इस याचिका में समग्र रूप में घरेलू उद्योग के लिए सूचना निहित है। इसकी घरेलू उत्पादकों ने विशेष रूप से द्विपक्षीय रक्षोपाय कदम को लागू किये जाने की मांग की है।

क. 3एफ इंडस्ट्री लिमि.,

- ख. अदानी विलमर लिमि.,
- ग. सी ओ एफ सी ओ इंटरनेशनल,
- घ. इमामी एग्रोटेक लिमि.
- ङ. जेमिनी इंडिब्ले फेड्स एंड ऑयल्स लिमि.
- च. गोकुल एग्रो रिसोर्सिस लिमि.,
- छ. लिबर्टी ऑयल मिल्स लिमि.,
- ज. ओजोन प्रोकाॅन प्रा. लिमि.,
- झ. रुचि सोया इंडस्ट्रीज लिमि. (6 यूनिट्स)

14. यह माना गया है कि इस याचिका को भारत में समान वस्तु के “समग्र रूप में घरेलू उत्पादकों” की ओर से दायर किया गया है और साल्वेंट एक्ट्रेचर एसोसिएशन ऑफ इण्डिया को इस जांच के उद्देश्य से घरेलू उद्योग के रूप में लिया गया है।

III. जांच की अवधि (पी ओ आई)

15. यह अवधि जनवरी – जून, 2019 को इस तथ्य के निर्धारण के उद्देश्य से जांच की अवधि (पी ओ आई) के रूप में मानी गई है कि क्या आर बी डी के आयातों में इतनी मात्रा में वृद्धि हुई है जिससे कि यह “बढ़ा हुआ आयात” है। कच्चे पाम आयल और संबद्ध वस्तुओं लागू सीमा शुल्क ने 1 जनवरी, 2019 से परिवर्तन हुआ है। न तो घरेलू कानून और न ही गैट (जी ए टी टी) के रक्षोपाय करार और अनुच्छेद XIX और न ही भारत और भारत – मलेशिया व्यापक आर्थिक सहयोग करार यद्यपि (द्विपक्षीय रक्षोपाय कदम) नियमावली, 2017 ने इस तथ्य को छोड़कर जांच की अवधि पर कई विशिष्ट दिशानिर्देश दिये गये हैं की संगत जांच की अवधि भारतीय उद्योग को गंभीर क्षति अथवा गंभीर क्षति के खतरे तथा बढ़े हुए आयात पर निकाले जाने वाले निष्कर्ष की अनुमति देने के लिए पर्याप्त रूप से लंबी होनी चाहिए। क्षति की जांच की अवधि को 2016 – 17, 2017 - 18, अप्रैल – दिसंबर, 2018 और जांच की अवधि के रूप में माना गया है। अप्रैल – दिसंबर, 2018 और जांच की अवधियों के लिए वर्तमान जांच परिणाम में आंकड़ों का उल्लेख पिछले वर्ष की अवधि के प्रयोग किये जाने के उद्देश्य से वार्षिकीकृत आधार पर किया गया है।

IV. सूचना का स्रोत

16. चूंकि संबद्ध वस्तुओं का समर्पित सीमा शुल्क कोड है अतः अप्रैल 2015 से जून 2019 तक की अवधि के लिए आयात संबंधी आंकड़ों पर डी जी सी आई एंड एस द्वारा प्रकाशित आयात निर्यात आंकड़ों के अनुसार विचार किया गया है। गंभीर क्षति के संबंध में सोल्वेंट एक्ट्रेचर एसो. ऑफ इण्डिया के द्वारा दी गयी सूचना पर विचार समग्र रूप से घरेलू उत्पादकों के लिए किया गया है।
17. गंभीर क्षति के संबंध में सूचना याचिकाकर्ताओं द्वारा समग्र रूप में घरेलू उत्पादकों के संबंध में उपलब्ध कराई गई है। जांच की शुरुआत करने के बाद, महानिदेशक ने सोल्वेंट एक्ट्रेचर एसो. ऑफ इण्डिया एवं संघ द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूची के अनुसार उत्पादकों को प्रश्नावली जारी की जिसमें उन्हें निदेश दिया गया कि वे निर्धारित प्रश्नावली के अनुसार सूचना उपलब्ध करायें। निम्नलिखित घरेलू उत्पादकों द्वारा उक्त सूचना उपलब्ध कराई गई है :

- क. इमामी एग्रोटेक लिमि.
- ख. लिबर्टी ऑयल मिल्स लिमि.
- ग. जेमिनी इंडिब्ले फेड्स एंड ऑयल्स लिमि.
- घ. अदानी विलमर लिमि.
- ङ. गोकुल एग्रो रिसोर्सिस लिमि.
- च. विमल ऑयल एंड फूड्स लिमि.
- छ. ओजोन प्रोकाॅन प्रा. लिमि.

18. महानिदेशक ने निम्नलिखित आधार पर क्षति और गंभीर क्षति के उत्पन्न होने पर विचार किया है।

- क. मानदंडों जैसे बाजार का हिस्सा, क्षमता, उत्पादन, घरेलू बिक्री, क्षमता का उपयोग, बिक्री का निर्धारण सबसे पहले घरेलू उत्पादकों के लिए समग्र रूप में किया गया है और उसके बाद भाग लेने वाली कंपनियों के लिए भी किया गया है।
- ख. मानदंडों जैसे लाभ, मजदूरी और रोजगार की जांच समेकित आधार पर सभी घरेलू उत्पादकों के संबंध में की गई है। इन मानदंडों का विश्लेषण भी उत्तर देने वाले घरेलू उत्पादकों के संबंध में अलग अलग आधार पर किया गया है।
19. गंभीर क्षति के खतरे के लिए, महानिदेशक ने इस सूचना पर विचार किया है जो याचिकाकर्ता द्वारा अपने आवेदन में और जांच की शुरुआत किये जाने के बाद प्रस्तुत की गई अतिरिक्त सूचना है। याचिकाकर्ता द्वारा जांच की शुरुआत किये जाने के बाद प्रस्तुत की गई सूचना की एक प्रति इन पक्षकारों के अवलोकन के लिये सार्वजनिक फाइल में रखी गई है जिससे कि वे अपनी टिप्पणियां यदि कोई हो, प्रस्तुत कर सकें जिस पर अंतिम निर्धारण के लिए विचार किया जायेगा।

V. संबद्ध देश से बढ़ा हुआ आयात

20. भारत – मलेशिया सी ई सी ए (करार) और भारत- आशियन ए आई एफ टी ए (करार) में नीचे किये गये उल्लेख के अनुसार सी पी ओ और आर बी डी पर सीमा शुल्क में कमी का प्रावधान किया गया।

एम आई सी ई सी ए अधिमान्य प्रशुल्क			
	प्रशुल्क लाइन	सी पी ओ	आर पी ओ
	आधार दर	80	90
	ईआईएफ*	72	82
के बाद नहीं	1.1.2012	68	78
	1.1.2013	64	74
	1.1.2014	60	70
	1.1.2015	56	66
	1.1.2016	52	62
	1.1.2017	48	58
	1.1.2018	44	54
	31.12.2018	40	45

ए आई एफ टी ए अधिमान्य प्रशुल्क			
	प्रशुल्क लाइन	सी पी ओ	आर पी ओ
	आधार दर	80	90
के बाद बाद	2010	76	86
	2011	72	82
	2012	68	78
	2013	64	74
	2014	60	70
	2015	56	66
	2016	52	62
	2017	48	58

	2018	44	54
	2019	40	50

21. यह देखा गया है कि कच्चा पाम ऑयल (सी पी ओ) और विचाराधीन उत्पाद के बीच सीमा शुल्क अंतर अप्रैल 2015 से दिसंबर, 2018 तक की अवधि के दौरान 10 प्रतिशत था। हालांकि, सीमा शुल्क के अंतर में 01.01.2019 से 5 प्रतिशत तक कमी आई। सीमा शुल्क अंतर में इस कमी के फलस्वरूप कच्चे पाम ऑयल के आयातों में परिणामी गिरावट के साथ संबद्ध आयातों में बहुत अधिक वृद्धि हुई है।

VI. मलेशिया से बढ़ा हुआ आयात

22. भारत – मलेशिया व्यापक आर्थिक सहयोग करार (द्विपक्षीय रक्षोपाय कदम) निमयावली, 2017 के अंतर्गत द्विपक्षीय रक्षोपाय शुल्क निमयावली के नियम 2(घ) में नीचे दिए गए अनुसार प्रावधान है :
- “बढ़े हुए आयात” का आशय मलेशिया से आयातों में चाहे वह स्वतंत्र रूप में हुआ हो अथवा घरेलू उत्पादन के सापेक्ष हुआ हो वृद्धि से है*
23. उक्त निमयावली में इस तथ्य की जांच की जानी अपेक्षित है कि क्या विचाराधीन उत्पाद के आयातों में स्वतंत्र रूप में अथवा सापेक्ष रूप में ऐसी मात्रा में वृद्धि हुई है जिससे कि वह “बढ़ा हुआ आयात” माना जाये। उक्त निमयावली में भारत में स्वतंत्र रूप में और आयातों की तुलना में दोनों में, भारत में उत्पादन और खपत की तुलना में इन आयातों का विश्लेषण अपेक्षित है। विचाराधीन उत्पाद के बढ़े हुए आयातों का विश्लेषण इस निमयावली के संबंध में किया गया है।

i. स्वतंत्र रूप में मलेशिया से आयात

24. आयातों की गति नीचे दी गई तालिका में दर्शायी गई है

क्र. सं.	अवधि	मात्रा (मी. ट.)		
		मलेशिया	अन्य देश	कुल आयात
1	2016-17	626,362	2,315,292	29,41,654
2	2017-18	376,136	2,308,482	26,84,618
3	2018-19	696,909	1,729,644	24,26,553
4	अप्रैल – दिसं. 2018 (वार्षिकीकृत)	271,099	1,986,498	22,57,597
5	जांच की अवधि (वार्षिकीकृत)	2,596,225	725,210	33,21,435
तिमाही आधार पर आयात (मी. ट.)				
1	क्यू 1 18-19	97,239	470,534	5,67,773
2	क्यू 2 18-19	78,879	640,816	7,19,695
3	क्यू 3 18-19	27,206	378,524	4,05,730
4	क्यू 4 18-19	493,584	239,771	7,33,355
5	क्यू 1 19-20	804,528	122,834	9,27,362

25. विचाराधीन उत्पाद के आयातों में स्वतंत्र रूप में जांच की अवधि में बहुत अधिक मात्रा में वृद्धि हुई है। जांच की अवधि के दौरान विचाराधीन उत्पाद के आयातों में शीघ्र और अत्यधिक वृद्धि हुई है। मलेशिया से आयातों में वृद्धि हुई है और यह 2016-17 में 626,362 मी. ट. से बढ़कर जनवरी-जून, 2019 में 2,596,225 मी. ट. (वार्षिकीकृत

आधार पर) हो गई है और इस प्रकार से यह 314 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। अन्य देशों से आयातों में गिरावट हुई है और यह 2016-17 में 2,315,292 मी. ट. से घटकर जनवरी-जून, 2019 (वार्षिकीकृत आधार पर) 7,25,210 मी. ट. हो गया है।

26. आयातों में तिमाही गति का विश्लेषण यह दर्शाता है कि अक्टूबर-दिसंबर, 2018 में आयात 27,206 मी. ट. था जो अचानक बढ़कर अप्रैल-जून, 2019 में 804,528 मी. ट. हो गया और इस प्रकार से यह लगभग 29 गुणा वृद्धि को दर्शाता है।

ii. **मलेशिया और अन्य देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयातों में वृद्धि का हिस्सा**

27. मलेशिया और अन्य देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयातों के हिस्से को नीचे दी गई तालिका में दर्शाया गया है :

क्र. सं.	अवधि	आयातों में हिस्सा (%)	
		मलेशिया	अन्य देश
1	2016-17	21%	79%
2	2017-18	14%	86%
3	2018-2019	29%	71%
4	अप्रैल - दिसं. 2018	12%	88%
5	जांच की अवधि वार्षिकीकृत	78%	22%
तिमाही आधार पर आयात			
1	क्यू1 18-19	17%	83%
2	क्यू2 18-19	11%	89%
3	क्यू3 18-19	7%	93%
4	क्यू4 18-19	67%	33%
5	क्यू1 19-20	87%	13%

28. यह नोट किया जाता है कि 2016-17 में मलेशिया से विचाराधीन उत्पाद का आयात भारत में कुल आयातों का 21 प्रतिशत था। आयातों में मात्रा वही रही और इसमें भारत में विचाराधीन उत्पाद के आयातों की तुलना में दिसंबर 2018 तक कोई वृद्धि नहीं हुई। हालांकि, मलेशिया से आयातों के हिस्से में जांच की अवधि के दौरान बहुत अधिक वृद्धि हुई। मलेशिया से संबद्ध वस्तुओं के आयातों में जांच की अवधि के दौरान बहुत अधिक मात्रा में 78 प्रतिशत तक वृद्धि हुई। मलेशिया से विचाराधीन उत्पाद के आयातों के समग्र हिस्से में आधार वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में लगभग 4 गुणा तक वृद्धि हुई है।

iii. **भारत में उत्पादन और खपत की तुलना में आयातों में वृद्धि**

29. भारत में उत्पादन और खपत की तुलना में खपत वस्तुओं के आयातों की गति नीचे दी गई तालिका में दर्शायी गई है :

क्र.सं.	अवधि	मलेशिया से आयात	भारतीय उत्पादन	भारतीय खपत	निम्नलिखित की तुलना में आया (%)	
		मी. ट.	मी. ट.	मी. ट.	उत्पादन	खपत
1	2016-17	626,362	4,247,839	7,190,365	15%	9%
2	2017-18	376,136	5,308,775	7,995,216	7%	5%
3	2018-19	696,909	5,070,583	7,510,304	14%	9%

4	अप्रैल – दिसं. 2018 (वार्षिकीकृत)	271,099	4,965,180	7,237,288	5%	4%
5	जांच की अवधि (वार्षिकीकृत)	2,596,225	4,847,732	8,174,382	54%	32%
6	क्यू1 18-19	97,239	952,452	1,527,291	10%	6%
7	क्यू2 18-19	78,879	1,269,789	1,990,599	6%	4%
8	क्यू3 18-19	27,206	1,501,645	1,910,075	2%	1%
9	क्यू4 18-19	493,584	1,346,697	2,082,338	37%	24%
10	क्यू1 19-20	804,528	1,077,169	2,004,852	75%	40%

30. यह नोट किया जाता है कि 2016 – 17 में मलेशिया से आयातित विचाराधीन उत्पाद और भारत में उत्पादों और खपत का क्रमशः 15 प्रतिशत और 9 प्रतिशत हुआ था। हालांकि, मलेशिया के हिस्से में पी. ओ. आइ. में क्रमशः 54 प्रतिशत और 32 प्रतिशत का उछाल आया। इस प्रकार से आयातों ने उत्पादन और खपत की तुलना में आयातों में बहुत अधिक वृद्धि को दर्शाया है। उत्पादन और खपत की तुलना में आयातों में वृद्धि को इतनी कम अवधि में बहुत अधिक माना गया है।

VII. गंभीर क्षति

31. गंभीर क्षति और गंभीर क्षति के खतरे की परिभाषा इस नियमावली के अंतर्गत नीचे दिये गये अनुसार दी गई है :
- (ग) गंभीर क्षति का आशय घरेलू उद्योग की स्थिति बहुत अधिक समग्र हानि से है; और
- (घ) गंभीर क्षति के खतरे का आशय उस गंभीर क्षति से है जो समस्त रूप से आसन्न है और जिसका निर्धारण तथ्यों के आधार पर और न कि केवल आरोप, अनुमान अथवा दूर की संभावना के आधार पर किया जायेगा।
32. इस प्रकार आयातों में वृद्धि ऐसी होनी चाहिए जिसके कारण घरेलू उद्योग की स्थिति में बहुत अधिक समग्र हानि होती हो
33. इस नियमावली के नियम-7 में आगे नीचे दिये गये अनुसार प्रावधान है :
- महानिदेशक अन्य बातों के साथ साथ निम्नलिखित सिद्धांतों पर विचार करने के बाद घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति अथवा गंभीर क्षति के खतरे का निर्धारण करेंगे अर्थात् :-
- (क) महानिदेशक परिमाण निर्धारित करने योग्य और वस्तुपरक प्रकृति के सभी संगत कारकों का मूल्यांकन करेंगे जिसका उस घरेलू उद्योग की स्थिति विशेष रूप से स्वतंत्र और सापेक्ष रूप में मूल वस्तु के आयातों में वृद्धि की दर और राशि, मूल वस्तु के बड़े हुए आयातों के द्वारा कब्जा किये गये घरेलू बाजार का हिस्सा, बिक्री, उत्पादन, उत्पादकता, क्षमता का उपयोग, लाभ और हानि और रोजगार स्तर में परिवर्तन पर प्रभाव पड़ता हो।
34. यह नोट किया जाता है कि उल्लिखित मानदंडों के मूल्यांकन में अलग अलग उद्योगों और स्थितियों की विशेषताओं पर विचार किया जाना आवश्यक है। इस कारण से महानिदेशक ने घरेलू उद्योग की स्थिति और वर्तमान मामले के तथ्यों के संबंध घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति की जांच की है। इस प्रकार से सभी उल्लिखित कारकों और किसी अन्य संगत कारकों की तकनीकी जांच के अलावा, यह आवश्यक है कि इस उद्योग की समग्र स्थिति का मूल्यांकन उन सभी कारकों को ध्यान में रखकर किया जाता है जिनका इस उद्योग की स्थिति पर प्रभाव पड़ता हो। तदनुसार, गंभीर क्षति और गंभीर क्षति के खतरे का विश्लेषण करने में सभी कारकों जिनका उल्लेख नियमावली में किया गया है और अन्य कारकों जो गंभीर क्षति अथवा गंभीर क्षति के खतरे का निर्धारण करने के लिए संगत हैं, पर विचार किया गया है।

गंभीर क्षति अथवा गंभीर क्षति के खतरे का निर्धारण इन सभी संगत कारकों जिनका उस उद्योग की स्थिति पर प्रभाव पड़ता हो, के आलोक में इस उद्योग की समग्र स्थिति के मूल्यांकन पर आधारित है।

35. नियम 3 (ख) में नीचे दिये गये अनुसार है

महानिदेशक परिमाण निर्धारित करने योग्य और वस्तुपरक प्रकृति के सभी संगत कारकों का मूल्यांकन करेंगे जिसका उस घरेलू उद्योग की स्थिति विशेष रूप से स्वतंत्र और सापेक्ष रूप में मूल वस्तु के आयातों में वृद्धि की दर और राशि, मूल वस्तु के बड़े हुए आयातों के द्वारा कब्जा किये गये घरेलू बाजार का हिस्सा, बिक्री, उत्पादन, उत्पादकता, क्षमता का उपयोग, लाभ और हानि और रोजगार स्तर में परिवर्तन पर प्रभाव पड़ता हो।

36. संबद्ध वस्तुओं के बड़े हुए आयातों के कारण घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति और गंभीर क्षति के खतरे की जांच इस नियमावली के अंतर्गत यथासूचीबद्ध निम्नलिखित कारकों का मूल्यांकन कर किया गया है :

क. स्वतंत्र और सापेक्ष रूप में आयातों में वृद्धि

37. यह नोट किया गया है कि संबद्ध वस्तुओं के आयातों में हाल की अवधि में स्वतंत्र रूप में तथा सापेक्ष रूप में बहुत अधिक वृद्धि हुई है। आयातों में वृद्धि स्वतंत्र रूप में तथा कुल आयातों, भारतीय उत्पादन और खपत की तुलना दोनों में हुई है। इसके अलावा, आयातों में वृद्धि को नोट किया जाता है कि क्या इस स्थिति की तुलना 2016-17 और जनवरी – जून, 2019 अथवा तीव्र वृद्धि की अवधि के ठीक पूर्व की अवधि से की जा सकती है। यह भी नोट किया जाता है कि पिछले तिमाही की तुलना में अप्रैल – जून, 2019 में बहुत अधिक वृद्धि हुई थी।

ख. उत्पादन और बिक्री

38. याचिकाकर्ता ने अनुरोध किया है कि उत्पादन का एकमात्र स्रोत या तो घरेलू अथवा आयात किया गया कच्चा माल है और केवल कच्चे माल का उपयोग विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन में होता है। उन्होंने यह भी दावा किया है कि उत्पादक फूल को तोड़ने से लेकर तेल की खपत के चरण तक प्रत्येक चरण में इस उत्पाद के भंडारण और उपयोग होने की अवधि कम होने के कारण लंबे समय तक न तो कच्चे माल के भंडार को रख सकते हैं अथवा तैयार उत्पाद के भंडार को रख सकते हैं। याचिकाकर्ता का यह भी तर्क था कि कच्चे माल से उत्पाद के उत्पादन के लिए खपत मानदंड न केवल उचित रूप से सन्निधीयुक्त है बल्कि इन्हें वैश्विक रूप से भी एक जैसा माना जा सकता है। याचिकाकर्ता ने सतत् पाम ऑयल पर राउंड टेबल से संगत सामग्री भी प्रस्तुत की है जिसमें सी पी ओ और आर बी डी ऑयल के बीच इनपुट – आउटपुट अनुपात दर्शाया गया है। याचिकाकर्ता ने यह भी अनुरोध किया है कि बिक्री उसी स्तर पर मानी जा सकती है जिस तरह से उत्पादन है चूंकि इस उत्पाद को लंबे समय तक भंडार में नहीं रखा जा सकता है।
39. उपर्युक्त को देखते हुए, सकल भारतीय उत्पादन और घरेलू बिक्री का आकलन इस प्रकार के खपत मानदंडों पर विचार करते हुए किया गया है कि इस उद्देश्य में, कच्चे माल की खपत (सी पी ओ) पर भारत में सी पी ओ के आयातों के आधार पर विचार किया गया है जो सार्वजनिक रूप से डी जी सी आई एंड एस द्वारा सूचित किया गया है।
40. उपर्युक्त पद्धति को अपनाते हुए घरेलू उत्पादन और बिक्री नीचे दिये गये अनुसार है :

क्र. सं.	अवधि	उत्पादन/ बिक्री	मांग
		मी. ट.	मी. ट.
1	2016-17	4,247,839	7,190,365
2	2017-18	5,308,775	7,995,216
3	2018-19	5,070,583	7,510,304
4	अप्रैल – दिसं. 18 अनुमानतः	4,965,180	7,237,288
5	जांच की अवधि अनुमानतः	4,847,732	8,174,382

41. यह नोट किया जाता है कि संबद्ध वस्तुओं की मांग में आधार वर्ष से गिरावट हो रही थी और घरेलू उत्पादन और बिक्री ने भी सादृश गिरावट को दर्शाया है। हालांकि, जांच की अवधि के दौरान मांग में वृद्धि हुई और यह वापस आधार वर्ष में प्रचलित स्तर तक पहुंच गया है जबकि भारतीय उत्पादन और बिक्री में आगे गिरावट हुई है। दूसरे शब्दों में जबकि मांग में जांच की अवधि में वृद्धि हुई, घरेलू उत्पादकों के उत्पादन और बिक्री में वृद्धि हुई। उत्पादन/ बिक्री में गिरावट अप्रैल – दिसंबर, 2018 की अवधि की तुलना जांच की अवधि (जनवरी – जून 2019) से किये जाने पर स्पष्ट होती है। भारतीय उत्पादन/ वृद्धि अप्रैल – दिसंबर, 2018 में 4,965,180 मी. ट. थी जो घटकर जांच की अवधि में 4,847,732 मी. ट. हो गयी अर्थात् इसमें 2.4 प्रतिशत से अधिक गिरावट हुई।

ग. क्षमता का उपयोग

42. क्षमता और क्षमता का उपयोग के व्यौरे नीचे दिये गये हैं :

अवधि	क्षमता (मी. ट.)	क्षमता का उपयोग	उत्पादन की मात्रा (मी. ट.)
2016- 17	1,39,00,000	31%	42,47,839
2017-18	1,39,00,000	38%	53,08,775
2018-19	1,39,00,000	36%	50,70,583
2019-20 (क्यू1)	1,39,00,000	21%	28,82,534
क्यू1 17-18	34,75,000	34%	11,80,275
क्यू2 17-18	34,75,000	40%	13,76,532
क्यू3 17-18	34,75,000	39%	13,50,830
क्यू4 17-18	34,75,000	40%	14,01,139
क्यू1 18-19	34,75,000	27%	9,52,452
क्यू2 18-19	34,75,000	37%	12,69,789
क्यू3 18-19	34,75,000	43%	15,01,645
क्यू4 18-19	34,75,000	39%	13,46,697
क्यू1 19-20	34,75,000	31%	10,77,169
अप्रैल – दिसं. '18	1,04,25,000	36%	37,23,885
जांच की अवधि जनवरी – जून '19	69,50,000	35%	24,23,866

43. यह नोट किया गया है कि घरेलू उद्योग ने अपनी क्षमता का बहुत कम उपयोग किया है और उनकी क्षमता का उपयोग जांच की अवधि के दौरान कम हो गया है।

घ. घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा

44. बाजार हिस्से की गति नीचे दी गई है :

क्र. सं.	अवधि	बाजार हिस्सा (%)	
		मलेशिया	भारतीय उद्योग
2	2016-17	9%	59%
3	2017-18	5%	66%
4	2018-19	9%	68%
5	अप्रैल – दिसं. '18	4%	69%
6	जांच की अवधि	32%	59%
7	जन. - मार्च, 2019	24%	65%
8	अप्रैल - जून, 2019	40%	54%

45. यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में गिरावट आई है जबकि मलेशिया से संबद्ध वस्तुओं के आयातों के बाजार हिस्से में पूर्व की वर्षों में तुलना में जांच की अवधि के दौरान वृद्धि हुई है।

ङ. रोजगार और उत्पादकता

46. याचिकाकर्ता ने यह दावा किया है कि विचाराधीन उत्पाद के प्रसंस्करण में लगाये गये मानव घंटों में वर्तमान अवधि में बहुत अधिक गिरावट आई है और *** लाख तक उत्पादन/ बिक्री की वार्षिक हानि पर विचार करते हुए (अक्टूबर – दिसंबर 2018 और जांच की अवधि में बिक्री पर विचार करते हुए) इस उत्पाद के लिए लगाये गये रोजगार में लगभग *** तक गिरावट आई है। इस तथ्य को देखते हुए कि संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन में गिरावट हुई है, उत्पादकता में गिरावट हुई है।

च. लाभ/ हानि

47. आयात किये गये कच्चे परिष्कृत तेल से संबद्ध वस्तुओं की शुद्ध लागत एवं उचित प्रतिफल के साथ लक्षित मूल्य नीचे दिये गये हैं :

कच्चे तेल का आयात	इकाई	जांच की अवधि वार्षिकीकृत
मात्रा (मी. ट)	मी. ट.	***
आयात मूल्य रु. लाख	रु. लाख	***
सी आई एफ रु./ मी. ट.	रु./ मी. ट.	***
सीमा शुल्क %	%	***
सीमा शुल्क राशि	रु./ मी. ट.	***
उपकर राशि	रु./ मी. ट.	***
पहुंच लागत	रु./ मी. ट.	***
खपत कारक		***
आर एम लागत		***
घटाये : उत्पाद से	रु./ मी. ट.	***
परिवर्तन लागत	रु./ मी. ट.	***
पाम ऑयल की शुद्ध लागत	रु./ मी. ट.	***
उचित प्रतिफल	5%	***
लक्षित कीमत	रु./ मी. ट.	***

48. उपर्युक्त लक्ष्य कीमत की तुलना में, मलेशिया से आयात किये गये आर बी डी पामोलिन की पहुंच कीमत नीचे दिये गये अनुसार है :

मात्रा (मी. ट.)	मी. ट.	2,596,225
सी आई एफ दर	रु./ मी. ट.	40,997
सीमा शुल्क	%	45%
सीमा शुल्क राशि	रु./ मी. ट.	18,449
उपकर राशि	रु./ मी. ट.	553
आर बी डी पामोलिन की पहुंच कीमत	रु./ मी. ट.	60,000

49. यह दावा किया गया है कि यदि घरेलू उत्पादक आयात किये गये संबद्ध वस्तुओं की कीमत का मुकाबला करते हैं तब उत्पादक अपनी लागत भी प्राप्त करने में सक्षम नहीं हो पायेंगे और इन्हें बहुत अधिक हानि होगी। वास्तव में यह नोट किया जाता है कि घरेलू उत्पादकों ने स्वयं आर बी डी तेल का आयात करना शुरू किया जिससे कि वे बाजार में बने रहे सकें। इसके परिणामस्वरूप, घरेलू उत्पादकों को बहुत अधिक उत्पादन और उसके परिणामस्वरूप बिक्री की हानि हुई है। इसके फलस्वरूप घरेलू उत्पादकों को लाभ में बहुत अधिक हानि हुई है। *** रु. पी एम टी के उचित लाभ पर विचार करते हुए, घरेलू उद्योग की अनुमानित लाभप्रदता में इस अवधि के दौरान बहुत अधिक गिरावट आई जिसे निम्नलिखित से नोट किया जाता है :

	बिक्री	लाभ
	मी. ट.	रु. करोड़
2016- 17	42,47,839	***
2017-18	53,08,775	***
क्यू1 18-19	9,52,452	***
क्यू2 18-19	12,69,789	***
क्यू3 18-19	15,01,645	***
क्यू4 18-19	13,46,697	***
क्यू1 19-20	10,77,169	***

50. यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग के अनुमानित लाभ में जांच की अवधि के दौरान बहुत अधिक गिरावट आई।

ख. कीमत ह्रास/ न्यूनीकरण और कीमत में कटौती

51. संबद्ध वस्तुओं की पहुंच कीमत की तुलना संबद्ध वस्तुओं के लिए तय की गई उचित कीमत से तुलना नीचे दी गई तालिका में दर्शायी गई है :

विवरण	इकाई	लागत
आर बी डी पाम ओलिन की उचित कीमत	रु./ मी. ट.	***
आर बी डी पामोलिन की पहुंच कीमत	रु./ मी. ट.	***
अंतर	रु./ मी. ट.	***

52. यह नोट किया जाता है कि आर बी डी पाल्मोलिन की पहुंच कीमत घरेलू उत्पादकों द्वारा अपेक्षित आर बी डी पाम और ओलिन की उचित कीमत के स्तर से बहुत कम है, यदि वे सी पी ओ का आयात करें और उसे विचाराधीन उत्पाद में प्रसंस्कृत करें। यह दर्शाता है कि इन आयातों के कारण घरेलू उत्पादकों की कीमतों पर उस सीमा तक दबाव पड़ रहा है कि घरेलू उत्पादक उस सीमा तक उत्पादन क्रियाकलाप ही नहीं कर रहे हैं। आयातों की पहुंच कीमत और उचित कीमत के बीच अंतर बहुत अधिक है जो मलेशिया के आयातों द्वारा कीमत में बहुत अधिक कटौती को दर्शाता है।

घरेलू उत्पादकों जिन्होंने आंकड़े उपलब्ध कराये हैं का क्षति विश्लेषण

53. समग्र रूप में घरेलू उत्पादकों के संबंध में इस उद्योग के कार्य निष्पादन के विश्लेषण के अलावा, महानिदेशक ने उन कंपनियों के कार्य निष्पादन का विश्लेषण किया है जिन्होंने जांच की शुरुआत के बाद सूचना उपलब्ध कराई। निम्नलिखित घरेलू उत्पादकों ने क्षमता, उत्पादन, बिक्री, रोजगार, मजदूरी, उत्पादकता और लाभ से संबंधित सूचना उपलब्ध कराई है।

- क. इमामी एग्रोटेक लिमि.
ख. लिबर्टी ऑयल मिल्स लिमि.
ग. जेमिनी इंडिब्ले फेड्स एंड ऑयल लिमि.
घ. अदानी विलमर लिमि.
ङ. गोकुल एग्रो रिसोर्सिस लिमि.
च. विमल ऑयल एंड फूड्स लिमि.
छ. ओजोन प्रोकाॅन प्रो. लिमि.

54. याचिका और बाद की प्रस्तुतियों से यह नोट किया जाता है कि इन कंपनियों का उत्पादन और बिक्री दिसंबर 2018 तक बढ़ रही थी। हालांकि, उत्पादन और बिक्री में 23 प्रतिशत (जांच की अवधि) और 31 प्रतिशत (अप्रैल – जून, 2019) तक गिरावट आई है। उत्पादन और बिक्री में गिरावट बहुत अधिक मानी गई है। इसके परिणामस्वरूप, इन कंपनियों के क्षमता के उपयोग और लाभ में भी बहुत अधिक गिरावट आई है। रोजगार और मजदूरी अधिकांश रूप में एक जैसी रही है। हालांकि उत्पादकता में बहुत अधिक गिरावट आई।

55. अलग अलग कंपनियों के कार्य निष्पादन की भी जांच उसी अवधि के लिए की गई है। यह नोट किया जाता है कि इन कंपनियों में से अधिकांश कंपनियों का उत्पादन, उत्पादकता और बिक्री दिसंबर 2018 तक बढ़ रही थी और इसमें जांच की अवधि के दौरान बहुत अधिक गिरावट आई

	उत्पादन (तिमाही)						
	जेमिनी	ओजोन	गोकुल	इमामी	अदानी	लिबर्टी	विमल
2016- 17	***	***	***	***	***	***	***
2017-18	***	***	***	***	***	***	***
क्यू 1 18-19	***	***	***	***	***	***	***
क्यू 2 18-19	***	***	***	***	***	***	***
क्यू 3 18-19	***	***	***	***	***	***	***
क्यू 4 18-19	***	***	***	***	***	***	***
क्यू 1 19-20	***	***	***	***	***	***	***

	क्षमता का उपयोग						
	जेमिनी	ओजोन	गोकुल	इमामी	अदानी	लिबर्टी	विमल
2016- 17	***	***	***	***	***	***	***
2017-18	***	***	***	***	***	***	***
क्यू 1 18-19	***	***	***	***	***	***	***
क्यू 2 18-19	***	***	***	***	***	***	***
क्यू 3 18-19	***	***	***	***	***	***	***
क्यू 4 18-19	***	***	***	***	***	***	***
क्यू 1 19-20	***	***	***	***	***	***	***

	उत्पादकता प्रति दिन						
	जेमिनी	ओजोन	गोकुल	इमामी	अदानी	लिबर्टी	विमल
2016- 17	***	***	***	***	***	***	***
2017-18	***	***	***	***	***	***	***
क्यू 1 18-19	***	***	***	***	***	***	***
क्यू 2 18-19	***	***	***	***	***	***	***
क्यू 3 18-19	***	***	***	***	***	***	***
क्यू 4 18-19	***	***	***	***	***	***	***
क्यू 1 19-20	***	***	***	***	***	***	***

	उत्पादन						
	जेमिनी	ओजोन	गोकुल	इमामी	अदानी	लिबर्टी	विमल
2016- 17	100	100	100	100	100	100	100
2017-18	193	1,747	145	124	111	173	40
क्यू 1 18-19	351	1,949	58	86	94	50	-
क्यू 2 18-19	301	2,159	86	117	105	46	-
क्यू 3 18-19	415	2,869	201	149	150	145	-
क्यू 4 18-19	368	2,360	91	131	124	202	-
क्यू 1 19-20	330	762	66	116	87	212	-

	क्षमता का उपयोग						
	जेमिनी	ओजोन	गोकुल	इमामी	अदानी	लिबर्टी	विमल
2016- 17	100	100	100	100	100	100	100
2017-18	193	1,747	145	124	111	173	40
क्यू 1 18-19	351	1,949	58	86	94	50	-

क्यू 2 18-19	301	2,159	86	117	105	46	-
क्यू 3 18-19	415	2,869	201	149	150	145	-
क्यू 4 18-19	368	2,360	91	131	124	202	-
क्यू 1 19-20	330	762	66	116	87	212	-
उत्पादकता प्रति दिन							
	जेमिनी	ओजोन	गोकुल	इमामी	अदानी	लिबर्टी	विमल
2016- 17	100	100	100	100	100	100	100
2017-18	193	1,747	145	124	111	173	40
क्यू 1 18-19	351	1,949	58	86	94	50	-
क्यू 2 18-19	301	2,159	86	117	105	46	-
क्यू 3 18-19	415	2,869	201	149	150	145	-
क्यू 4 18-19	368	2,360	91	131	124	202	-
क्यू 1 19-20	330	762	66	116	87	212	-

निष्कर्ष

56. उपरोक्त विश्लेषण से, इस प्रकार अनंतिम रूप से यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि विचाराधीन उत्पाद के आयातों में स्वतंत्र रूप में और भारत में सकल आयातों, भारतीय उत्पादन और खपत की तुलना में बहुत अधिक वृद्धि हुई है। मलेशिया से आयातों में अचानक बहुत अधिक वृद्धि के फलस्वरूप, घरेलू उत्पादकों को उत्पादन, बिक्री, क्षमता का उपयोग, बाजार हिस्से, लाभ में उस उत्पाद के लिए प्रसंस्करण क्रिया कलाप और प्रसंस्करण के लिए तैनात मानव शक्ति में बहुत अधिक गिरावट के संबंध में गंभीर क्षति हुई है। विभिन्न मानदंडों के संबंध में घरेलू उत्पादकों के कार्य निष्पादन पर विचार करते हुए, आगे की जांच जिसमें सत्यापन शामिल है के लंबित रहने तक अनंतिम रूप से यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि घरेलू उद्योग को मलेशिया से विचाराधीन उत्पाद के बड़े हुए आयातों के फलस्वरूप गंभीर क्षति हुई है।

VIII. गंभीर क्षति का खतरा

57. इस नियमावली में नीचे दिये गये अनुसार प्रावधान है :
- “गंभीर क्षति के खतरे” का आशय उस गंभीर क्षति से है जो स्पष्ट रूप से आसन्न है और जिसका निर्धारण तथ्यों और न केवल आरोप, अनुमान अथवा दूर की संभावना के आधार पर किया जायेगा।
58. यू एस के पैनल – लैंब ने यह माना कि जांच की अवधि के अंत के संबंधित उपलब्ध हाल के आंकड़ों पर ध्यान देना गंभीर क्षति के खतरे के विश्लेषण की भावी उन्मुक्त प्रकृति को देखते हुए तर्कसंगत है। संबंधित उद्धरण नीचे दिया गया है :

“हमारे विचार से, क्षति के विश्लेषण की भविष्य उन्मुख प्रकृति के कारण यह तार्किक प्रतीत होगा कि जांच की अवधि के आरंभ में घटनाएं इस अवधि के अंत में हुई घटनाओं की तुलना में कम महत्वपूर्ण हैं। जबकि एस जी करार में जांच में स्वीकार किये जाने के लिए समय अवधि का उपयुक्त अवधि का उल्लेख नहीं है, अर्जेंटीना – फूटवियर में अपीलीय निकाय और यह पैनल दोनों ने कुछ सीमा तक इस मुद्दे को माना। दोनों ने यह निष्कर्ष निकाला कि (वास्तविक गंभीर क्षति जांच निष्कर्ष के लिए) सबसे हालिया आंकड़े स्पष्ट रूप से सबसे अधिक संगत थे। विशेष रूप में अपीलीय निकाय ने यह उल्लेख किया कि ‘संगत जांच की अवधि को बहुत विगत हाल में समाप्त नहीं होना चाहिए, जांच की अवधि विगत हाल होनी चाहिए।’

यह देखते हुए कि गंभीर क्षति का खतरा आसन्न अत्यधिक समग्र हानि से संबंधित है अर्थात् यह तत्काल भविष्य में घटना होगी, वह सिद्धांत वर्तमान गंभीर क्षति के निर्धारण से तुलना किये जाने वाले क्षति निर्धारणों के लिए निश्चित रूप से सही होना चाहिए। यह इस दृष्टिकोण का समर्थन करता है कि यू एस आई टी सी का जांच की अवधि के समाप्त होने से सबसे हाल में उपलब्ध आंकड़ों पर ध्यान केंद्रित करना सही था। हम यह भी मानते हैं कि 1997 से और 1998 के मध्य से प्राप्त आंकड़ों में समुचित और तर्कसंगत समयावधि शामिल है यदि निकट भविष्य में मौजूदा प्रवृत्तियों का मूल्यांकन करते हुए अनुमानों के द्वारा इसकी पुष्टि की जाये जिससे कि भावी विश्लेषण सुनिश्चित हो सके जिसकी क्षति के निर्धारण में आवश्यकता होती है।

इस कारण से हम यह मानते हैं कि समग्र जांच की अवधि के कार्यकाल के बजाय जांच की अवधि के अंत में (अर्थात् एक वर्ष और नौ महीने) घटनाओं के संबंध में अपने निर्धारण को आधारित करते हुए, यू एस आई टी सी ने इस तथ्य का वैध मूल्यांकन करने के लिए पर्याप्त रूप से हाल के आंकड़ों का विश्लेषण किया है कि क्या बहुत अधिक समग्र हानि निकट भविष्य में 'आसन्न' थी। उसी संकेत के द्वारा हम यह भी मानते हैं कि भविष्य में विभिन्न उद्योग के संकेतकों के लिए अनन्य रूप से अनुमानों पर विश्वास करने के बजाय विगत हाल की घटनाओं के बारे में आंकड़ों पर अपने निर्धारण को आधारित कर यू एस आई टी सी में वस्तुपरक और मात्रा निर्धारण योग्य तथ्यों और 'न केवल आरोप, अनुमान अथवा दूर की संभावना' के आधार पर अपने खतरे का निर्धारण किया

59. यू एस पैनल की रिपोर्ट – लैंब ने अपीलीय निकाय द्वारा बाद में जांच परिणाम की समीक्षा नहीं की जो इस प्रश्न का समाधान करता था कि जैसे ही आयातों में वृद्धि के कारण पहले ही कुछ सीमा तक क्षति हुई है, गंभीर क्षति के खतरे के मौजूद होने का औचित्यपूर्ण तरीके से निर्धारण करने के उद्देश्य से अतिरिक्त बड़े हुए आयातों की आवश्यकता नहीं है। संगत उद्धरण नीचे दिये गये अनुसार है :

“शिकायतकर्ता आगे यह दावा करते हैं कि अपने खतरों के विश्लेषण का बचाव करने में आयातों में भविष्य में होने वाली वृद्धि के अनुमानों का यू एस द्वारा संदर्भ लेना गंभीर क्षति के खतरे के साथ 'बड़े हुए आयातों का खतरा' के समान होता है जो अर्जेटीना – फूटबियर पैनल ने अनुमति दिये जाने लायक नहीं माना आमतौर पर हम शिकायतकर्ता के इस तर्क से सहमत हैं कि इस प्रकार के बड़े हुए आयातों के खतरे को गंभीर क्षति के खतरे के बराबर नहीं माना जा सकता है। हालांकि, हमारा यह मत है कि यह वह नहीं है जो यू एस आई टी सी में इस मामले में किया है। इसके अलावा, हम यह भी संभव मानते हैं कि जांच की अवधि के अंत में और अधिक बढ़ते हुए बिना अपेक्षाकृत अधिक अवधि के लिए उच्च स्तर पर आयात के जारी रहने से, यदि नहीं रोका गया, गंभीर क्षति हो सकती है (अर्थात् गंभीर क्षति होने का खतरा उत्पन्न हो सकता है)। अर्थात्, यदि किसी निर्धारित समय में बड़े हुए आयातों के कारण गंभीर से कम क्षति होती हो तब यह आवश्यक रूप से सही नहीं है कि गंभीर क्षति के खतरे को और अधिक वृद्धि के द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है अर्थात् अतिरिक्त बड़े हुए आयातों के कारण ऐसा हो सकता है। **हमारे विचार से, किसी मामले में विशेष परिस्थितियों में पहले से हाल में बड़े हुए स्तर पर आयातों का जारी रहना इस प्रकार के खतरे को उत्पन्न करने के लिए पर्याप्त हो सकता है।**

60. यह नोट किया जाता है कि मलेशिया से सतत वस्तुओं का आयात भारतीय बाजार में स्वतंत्र रूप में तथा भारत में उत्पादन और खपत की तुलना में बहुत अधिक बढ़ी हुई मात्राओं में हो रहा है। घरेलू उद्योग की क्षमता का कम उपयोग किया गया था और मलेशिया से अत्यधिक आयातों के कारण इस स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। संबद्ध वस्तुओं के आयातों की पहुंच कीमत और संबद्ध वस्तुओं की उचित कीमत के बीच के अंतर पर विचार करते हुए, मलेशिया के पास बहुत अधिक मात्रा में क्षमताओं के साथ साथ उनके अत्यधिक निर्यात उन्मुखीकरण का तथ्य यह दर्शाता है कि मलेशिया से संबद्ध वस्तु संभवतः लाभप्रदाय रहेंगे, जिसके कारण घरेलू उद्योग को क्षति का लगातार खतरा बना रहेगा। गंभीर क्षति के खतरे को निम्नलिखित कारकों के द्वारा स्थापित किया गया है :

- क. घरेलू और आयात किये गये इस्पात के बीच कीमत में अंतर के फलस्वरूप मलेशिया से संबद्ध वस्तुओं के आयातों वृद्धि हुई है।
- ख. मलेशिया के उत्पादकों के पास बहुत अधिक मात्रा में अप्रयुक्त क्षमताएं हैं। इसके फलस्वरूप, मलेशिया के उत्पादकों और निर्यातक सतत् रूप से संभव सीमा तक अतिरिक्त बाजारों की तलाश कर रहे हैं।
- ग. इस उत्पाद की मांग बढ़ रही है और भारतीय बाजार व्यापक और कीमत संवेदनशील है।
- घ. चूंकि आयात किये गये सी पी ओ में से घरेलू उत्पादकों की बिक्री की लागत और आर बी डी तेल की आयात कीमत में बहुत अधिक अंतर है। अतः घरेलू उत्पादकों ने प्रसंस्करण क्रियाकलापों में कटौती की और पी सी ओ से आयात करना शुरू किया।
61. उपर्युक्त देखते हुए अनंतिम रूप से यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि मलेशिया से संबद्ध वस्तुओं के बढ़े हुए आयातों के कारण घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति हुई है। इसके अलावा, घरेलू उद्योग को मलेशिया से आयातों के कारण गंभीर क्षति के निरंतर खतरे का सामना करना पड़ा है।

IX. कारणात्मक संबंध

62. इन मानदंडों जिनका ऊपर में एक एक करके उल्लेख किया गया है, का व्यापक मूल्यांकन यह दर्शाता है कि गंभीर क्षति और गंभीर क्षति के खतरे बढ़े हुए आयातों के कारण हो रहे हैं। कारणात्मक कार्य संबंध का निर्धारण करने के उद्देश्य से, यह वस्तुपरक और मात्रा निर्धारित करने योग्य प्रकृति के सभी संगत कारकों जिसका उद्योग की इस स्थिति पर प्रभाव पड़ता हो, का मूल्यांकन किया गया है। वर्तमान मामले में, इस संबंध में निम्नलिखित बिंदु संगत हैं --
- क. विचाराधीन उत्पाद के आयातों में जांच की अवधि में स्वतंत्र रूप से तथा सापेक्ष रूप में बहुत अधिक वृद्धि हुई है।
- ख. घरेलू उत्पादकों के बाजार हिस्से में कमी आई है जबकि मलेशिया से आयातों के बाजार हिस्से में वृद्धि हुई है।
- ग. आयात की पहुंच कीमत संबद्ध वस्तुओं की उचित कीमत की तुलना में पर्याप्त रूप से कम है।
- घ. घरेलू उत्पादक बाजार में अपनी मौजूदगी को बनाये रखने के उद्देश्य से इन वस्तुओं का आयात करने के लिए बाध्य हैं।
- ङ. घरेलू उत्पादकों की बिक्री और उसके परिणामस्वरूप उत्पादन, क्षमता का उपयोग, तैनात मानव शक्ति और लाभ ने बढ़े हुए आयातों के फलस्वरूप गिरावट आई है।
63. इस प्रकार से यह स्पष्ट है कि घरेलू उद्योग को क्षति बढ़े हुए आयातों के कारण हुई है और मलेशिया से संबद्ध वस्तुओं के बढ़े हुए आयातों और घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति तथा गंभीर क्षति के खतरे के बीच कारणात्मक संबंध है।

X. नाजुक परिस्थिति

64. नियम 8 में यह निर्धारित किया गया है कि, महानिदेशक तेजी से इस जांच को करने की प्रक्रिया करेंगे और नाजुक परिस्थितियों में जहां स्पष्ट साक्ष्य है, कि बढ़े हुए आयातों के कारण घरेलू उद्योग को क्षति हुई है अथवा गंभीर क्षति होने का खतरा हो रहा है और जहां अनंतिम द्विपक्षीय रक्षोपाय कदम लागू किये जाने में विलंब से क्षति होगी जिसे पूरा करना मुश्किल होगा, मूल वस्तु के बढ़े हुए आयातों के फलस्वरूप घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति अथवा गंभीर क्षति के खतरे के संबंध में प्रारंभिक जांच परिणाम रिकार्ड कर सकते हैं। चूंकि याचिकाकर्ता ने रक्षोपाय कदम को तत्काल लागू किये जाने का अनुरोध किया। अतः याचिकाकर्ता से अनुरोध की जांच इस मामले की कानूनी आवश्यकताओं और तथ्यों के आलोक में की गई थी। यह नोट किया जाता है कि
- क. भारत में विचाराधीन उत्पादन के निर्यात में बहुत अधिक वृद्धि दर्शायी है। मलेशिया से संबद्ध वस्तुओं के आयातों में 2016-17 में 626,362 मी. ट. से जनवरी – जून 2019 में 2,596,225 मी. ट. तक वृद्धि हुई (वार्षिकीकृत आधार पर) और इस प्रकार से 314 प्रतिशत की वृद्धि दृष्टिगत हुई है।

- ख. आयातों में तिमाही गति यह दर्शाती है कि आयात अक्टूबर – दिसंबर, 2018 में 27,206 मी. ट. मात्र था जो अचानक बढ़कर अप्रैल – जून, 2019 में 804528 मी. ट. हो गई और इस प्रकार से यह लगभग 29 गुणा वृद्धि ही दर्शाती है।
- ग. कम कीमतों पर आयातों में इस वृद्धि के फलस्वरूप जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की पर्याप्त क्षमताएं बेकार हो गई हैं। यद्यपि घरेलू उद्योग के पास विशाल मात्रा में संस्थापित क्षमता है फिर भी यह विचाराधीन उत्पाद के घरेलू मांग में वृद्धि के बावजूद संबद्ध वस्तुओं के अपने उत्पादन में वृद्धि करने में सक्षम नहीं है।
- घ. घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में बहुत अधिक मात्रा में गिरावट आई है।
65. यह उल्लेखनीय है कि ऐसे कारक हैं जो वर्तमान मामले में नाजुक परिस्थितियों के रूप में मौजूद हैं जिन्होंने भारतीय उद्योग के समग्र कार्य निष्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है और घरेलू उत्पादकों को गंभीर क्षति पहुंचाई है और आगे गंभीर क्षति के होने का खतरा है। इस कारण से घरेलू उद्योग को आगे क्षति को रोकने के उद्देश्य से आयातों में इस उद्घाल को रोकने के लिए इसे उपयुक्त माना गया है।

XI. निष्कर्ष और सिफारिशें :

66. उपर्युक्त प्रारंभिक जांच परिणाम के आधार पर, अनंतिम रूप से यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि विचाराधीन उत्पाद के बढ़े हुए आयातों के कारण घरेलू उत्पादकों को गंभीर क्षति हुई है और इससे गंभीर क्षति होने का खतरा उत्पन्न हो रहा है। फलस्वरूप, घरेलू उत्पादन/ बिक्री में बहुत अधिक गिरावट आई जिसके फलस्वरूप जांच की अवधि में क्षमता के उपयोग में गिरावट आई। घरेलू उद्योग बाजार में अपनी मौजूदगी को बनाये रखने के लिए संबद्ध वस्तुओं का आयात करने के लिए बाध्य रहा है। अपेक्षाकृत कम कीमतों पर आयातों से घरेलू उद्योग की कीमतों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। इस प्रकार से यह माना गया है कि नाजुक परिस्थितियां वहां मौजूद होती हैं जहां रक्षोपाय कदमों के लागू किये जाने में विलंब के कारण घरेलू उत्पादकों को अपूर्णीय क्षति होगी। द्विपक्षीय रक्षोपाय शुल्क लागू किये जाने के संबंध में, द्विपक्षीय रक्षोपाय नियमावली के नियम 9 में नीचे दिये गये अनुसार उल्लेख है :

9. अनंतिम द्विपक्षीय रक्षोपाय कदम लागू करना -

- (1) केंद्र सरकार महानिदेशक के आरंभिक जांच परिणामों के आधार पर निम्नलिखित कर सकती है -
- (क) जब द्विपक्षीय रक्षोपाय कदम उठाया जाता है उस दिन से व्यापार करार के अंतर्गत उपलब्ध कराई गई मूल वस्तु पर सीमा शुल्क की किसी दर में आगे कटौती को स्थगित कर सकती है; अथवा
- (ख) मूल वस्तु पर सीमा शुल्क की दर को इस स्तर तक बढ़ा सकती है जो निम्नलिखित में से कमतर से अधिक नहीं होगी;
- (i) जब द्विपक्षीय रक्षोपाय कदम उठाया जाये उस दिन से लागू मूल वस्तु पर सीमा शुल्क की सर्वाधिक वरीयता प्राप्त देश के लिये लागू दर; अथवा
- (ii) जांच की अवधि के आरंभ से ठीक पहले दिन को लागू मूल वस्तु पर सीमा शुल्क की सर्वाधिक वरीयता प्राप्त देश के लिये लागू दर।
- (2) उप-नियम (1) के अंतर्गत द्विपक्षीय रक्षोपाय कदम इसके लागू किये जाने की तिथि से अधिकतम दो सौ दिनों की अवधि के लिए ही लागू रहेगा।

67. उपर्युक्त की जांच करने के बाद भारत – मलेशिया व्यापक आर्थिक सहयोग करार (द्विपक्षीय रक्षोपाय कदम) नियमावली 2017 के नियम 9 के संबंध में अनंतिम द्विपक्षीय रक्षोपाय शुल्क लागू करना उपयुक्त माना गया है। तदनुसार, महानिदेशक 180 दिनों के लिए 5 प्रतिशत तक संबद्ध वस्तुओं पर शुल्क में वृद्धि की सिफारिश करते हैं जिसे घरेलू उद्योग के हित की रक्षा करने के लिए उपयुक्त माना गया है।

XII. आगे की प्रक्रिया :

68. नीचे दिये गये अनुसार प्रक्रिया का पालन प्रारंभिक जांच परिणाम को अधिसूचित करने के बाद किया जायेगा :
- i. महानिदेशक प्रारंभिक जांच परिणामों के जारी होने की तिथि से 21 दिनों के भीतर सभी ज्ञात हितबद्ध पक्षकारों से प्रारंभिक जांच परिणामों पर टिप्पणियां आमंत्रित करते हैं। उसने प्राप्त टिप्पणियों की जांच अंतिम जांच परिणामों में की जायेगी।

- ii. महानिदेशक सभी हितबद्ध पक्षकारों को इस जांच के संबंधित अपने विचारों को प्रस्तुत करने के लिए एक अवसर देने हेतु मौखिक सुनवाई आयोजित करेंगे। मौखिक सुनवाई के दौरान उठाये गये मुद्दों और चिंताओं की जांच अंतिम जांच परिणामों में की जायेगी।
- iii. मौखिक सुनवाई की तिथि डी जी टी आर की वेबसाइट (dgtr.gov.in) पर घोषित की जाएगी।
- iv. महानिदेशक उस सीमा तक सत्यापन करेंगे जिस सीमा तक वे इसे आवश्यक मानेंगे।

सुनील कुमार, अपर सचिव एवं महानिदेशक

MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

NOTIFICATION

(Bilateral Safeguard Investigation)

New Delhi, the 26th August, 2019

[Case No: (SG) 04/2019]

Subject: Preliminary findings of Bilateral Safeguard Investigation concerning imports of “Refined Bleached Deodorised Palmolein and Refined Bleached Deodorised Palm Oil” into India from Malaysia under India-Malaysia Comprehensive Economic Cooperation Agreement (Bilateral Safeguard Measures) Rules, 2017

F. No. 22/4/2019-DGTR.— Having regard to the Article 5 of the Comprehensive Economic Cooperation Agreement between the Government of the Republic of India and the Government of Malaysia (CECA) and India-Malaysia Comprehensive Economic Cooperation Agreement (Bilateral Safeguard Measures) Rules, 2017 thereof.

A. Procedure

Whereas, an application had been filed under India-Malaysia Comprehensive Economic Cooperation Agreement (Bilateral Safeguard Measures) Rules, 2017 (hereinafter also referred to as the “said Rules” or “bilateral safeguard rules”) by the Solvent Extractors’ Association of India on behalf of the Indian domestic producers, through M/s TPM Consultants, New Delhi alleging increased imports of “Refined Bleached Deodorised Palm Oil” and “Refined Bleached Deodorised Palmolein” (hereinafter also referred to as the “product under consideration” or “PUC” or subject goods) from Malaysia (also referred to as subject country) causing serious injury and threat of serious injury to the domestic producers of like or directly competitive product in India.

1. Having satisfied that the requirements of article 4 of Bilateral safeguard rules were met, Bilateral safeguard investigation into increased imports of “Refined Bleached Deodorised Palm Oil” and “Refined Bleached Deodorised Palmolein” from Malaysia was initiated vide notice of initiation dated 14th August, 2019, published in the Gazette of India, Extraordinary.
2. A copy of the Notice of Initiation dated 14th August, 2019 along with copy of non-confidential version of the application filed by the domestic industry were forwarded to the Central Government in the Ministry of Commerce, Ministry of Finance, other administrative ministries, Government of Malaysia through its High Commission in India, and other interested parties as mentioned in the application, in accordance with Rule 5(2) and 5(3) of the said Rules.
3. Questionnaire was sent to the following foreign producers of the product in Malaysia
 - i. Felda Marketing Services Son Bhd
 - ii. Golden Jomalina Food Industries Son Bhd
 - iii. 101 Edible Oils Son Bhd

- iv. Kl-Kepong Edible Oils Son Bhd
 - v. Mewaholeo Industries Son Bhd
 - vi. Ngo Chew Hong Oils & Fats (M) Son
 - vii. Southern Edible Oil Industries (M) Son
 - viii. Kwantas Oil Son Bhd
 - ix. Sarawak Oil Palm Berhad
 - x. Siam Derby Oils Langat Refinery
 - xi. Golden Agri Resources Ltd
 - xii. Wilmar International
4. Interested parties were requested to make their views known in writing within 30 days of the initiation notice.
5. The petitioners in their application have submitted as follows
- a. Application for safeguard measures under the Agreement has been filed by Solvent Extractors' Association of India and therefore it should be considered that the application has been filed on behalf the producers of "Refined Bleached Deodorised Palm Oil" and "Refined Bleached Deodorised Palmolein" in India.
 - b. The product under investigation is "Refined Bleached Deodorised Palm Oil" and "Refined Bleached Deodorised Palmolein" (also known as RBD Palm Oil and RBD palmolein, respectively), falling under the HS code 15119010 and 15119020.
 - c. Product under consideration is commonly used to formulate trans-free fats such as margarine, shortening and vegetable ghee.
 - d. There are various producers who are member of the Association and nine of them have supported the petition.
 - e. Present application is by an association of domestic producers, it should be considered that the application has been filed on behalf of the domestic producers.
 - f. The association does not maintain individual producer's data such as production, sales, stocks, profits, etc. in view of the fact that this is commercially sensitive data and the association is constrained not to undertake this activity in view of Competition laws in the Country.
 - g. Information on domestic production has been derived from two sources (a) domestic crude palm oil (CPO) production (b) from imported crude palm oil.
 - h. Petitioner have derived gross Indian production by applying the conversion factor from Crude Palm Oil to subject goods considering that one MT raw material (CPO) produce 0.95 MT Refined palm oil. One MT refined palm oil produces 0.80 MT RBD oil.
 - i. Palm oil is semi-solid at room temperature (20°C). The liquid portion could be physically separated from the solid portion of palm oil by fractionation. After fractionation the liquid portion is called "palm olein" which is commonly bottled and sold as cooking oils. The solid fat portion is called "palm stearin" which is not under the scope of the product under consideration.
 - j. The standard rate applicable on subject goods is 100%. However, the applied rate are low due to Preferential Custom Duty under Preferential Tariff Agreements (CECA with Malaysia) & (AIFTA), which were notified vide Notification No. 82/2018 & 84/2018 both dated 31.12.2018. The applied rate of custom duty have been much below the level of rates provided for in the AIFTA and CECA Agreement and the difference between the custom duty for CPO and subject goods was 10%. The applied rates increased significantly in March 2018. It was only after this that the custom duty rates applicable under CECA and ASEAN became relevant.
 - k. The petitioner has filed this application pursuant to the Comprehensive Economic Cooperation Agreement entered into by Malaysia and Indian Government.
 - l. Pursuant to Malaysia CECA Agreement, the duty on imports of Crude Palm Oil (raw material of subject goods) from Malaysia has been reduced to 40% whereas the duty on subject goods has been reduced to 45%, vide Notification No. 82/2018 dated 31.12.2018. Thus, the difference between the duty on Crude Palm Oil and subject goods is a mere 5%.
 - m. The difference between duty on Crude Palm Oil and subject goods have always been 10%. Following the reduction of duty difference from 10% to 5% between Crude Palm Oil and subject goods, imports from Malaysia of subject goods has increased significantly.

- n. There is significant increase in the import volumes in the POI. The imports have increased by 516% from 2015-16 to the POI. Imports of product concerned into India increased significantly in absolute terms and in relation to production, consumption and share in imports.
- o. The imports in relation to production and consumption have also increased significantly. Imports constituted 8% of share in Indian production in 2015-16 which increased to 73% in the POI. Similarly, imports constituted 5% of share in Indian consumption in 2015-16 which increased to 32% in the POI.
- p. Imports from Malaysia constituted merely 17% of total Indian imports which in 2015-16 increased to 78% of the total imports in the proposed POI.
- q. Imports into India are largely from Indonesia and Malaysia. But Malaysia has duty advantage for RBD Palmolein under India – Malaysia CECA Agreement, so the country is now flooded with subject goods from Malaysia.
- r. Like product being produced by the domestic industry is the same as the imported product, i.e., “Refined Bleached Deodorised Palm Oil” and “Refined Bleached Deodorised Palmolein”. The domestic product is comparable to the imported product.
- s. The industry is suffering from gross underutilization of production capacities. To compound the difficulties of the domestic producers, the sudden surge in imports is further impacting the capacity utilization of the domestic producers in India.
- t. Petitioner has submitted that that since the product cannot be kept in stock for long, they have considered production as sales.
- u. Production and sales of the Indian industry has declined significantly. Whereas the demand for the product declined from 8,095,565 MT (2015-16) to 7,982,537 MT (POI annualised), production and consequently sales of the domestic industry declined from 5,558,240 MT (2015-16) to 4,833,716 MT (POI). The production of the domestic industry thus declined by 7.25 lacs MT, valued at around Rs. 3,000 crores, whereas demand for the product declined only by 1.13 lacs MT.
- v. Capacity utilization of the industry has declined very significantly. The Indian industry is not utilizing even half of its capacities and then capacity utilization declined to mere 31% in Q1 of 2019-20.
- w. Decline in production and capacity utilization is evident even from the decline in imports of crude palm oil. The imports of CPO declined sharply during this period.
- x. Market share of Indian industry has declined whereas market share of the imports have increased. Whereas the Indian producers were earlier holding 69% market share (2015-16), the same has declined to 61% (Apr.-June, 2019).
- y. The subject imports are significantly undercutting the prices of the domestic industry. Thus, if the Indian producers import the CPO, process the same into RBD oil and sell RBD oil in the market, they will not be able to recover even processing costs and would incur significant financial losses.
- z. The profits of the domestic industry has declined by about Rs. 268 crores in Jan.-June, 2019 as compared to the period April-Dec., 2018, considering loss of sales of about 7.6 lacs MT during this period (actual and potential loss), and a reasonable minimum profit of Rs. 2500 pmt that any refiner earns. The profits of the industry were increasing till Dec., 2018.
- aa. The Indian industry is operating their plant below 1/3rd of their capacities. Whereas the consumption of RBD in the country is in the region of 80 lacs MT, the country has capacities in the region of 130 lac MT. Imports of RBD oil are thus totally unnecessary.
- bb. Number of man-hours deployed in processing of product under consideration has declined in the current period. Considering annual loss of production to the extent of 20 lacs, the employment deployed for the product has declined by about 3,000.
- cc. The productivity of the Indian industry has declined significantly in the POI.
- dd. In addition to the serious injury already caused, imports are threatening serious injury as established by the following
 - i. The volume of imports has increased significantly in a relatively short period.
 - ii. Significant share in the domestic market is already held by the imports and such shares are increasing.
 - iii. The difference between domestic price and imported product is quite significant, as established by the import price of CPO and RBD Palmolein, after due adjustments for processing costs & expenses.

- iv. Malaysia holds huge production base and exports quite significant volumes. The fact that the imports have increased so rapidly in itself is clearly indicative of the likely damage that can be caused to the domestic processors.
- ee. There are no other factors that may be attributing to the serious injury to the domestic industry other than increased imports.
- ff. The landed price of imports is significantly lower than the selling prices of the domestic industry.
- gg. The domestic industry is losing sales opportunities as well as normal margin. Consequently, sales, profits, return on investment and cash flow is declining due to continued presence of low price imports.
- hh. Increased imports have led to increase in market share of imports and reduction in market share of the domestic industry.
- ii. The petitioner has requested safeguard measure as provided under India-Malaysia Comprehensive Economic Cooperation Agreement (Bilateral Safeguard Measures) Rules, 2017. The price difference between the target price, considering the import price of crude, processing costs involved and reasonable profit (5%) and landed price of imports is about 18%.
- jj. The purpose of seeking safeguard measure is to enable the domestic industry to improve its capacity utilization so that the domestic industry is able to survive.
- kk. The petitioner has requested safeguard measures for one year. Petitioner has also requested for imposition of provisional safeguard measure. It was submitted that the interim measures are imperative in view of the steep deterioration in performance of the domestic industry as a result of increased imports of the product under consideration.
- ll. It was also submitted that the imports from Malaysia has increased significantly whereas the production, sales and resultantly the capacity utilization of Indian industry has declined significantly.

B. Analysis of submissions made by petitioners for provisional measures

6. The petitioners request for imposition of provisional bilateral safeguard measures has been examined. Rule 8 of India-Malaysia Comprehensive Economic Cooperation Agreement (Bilateral Safeguard Measures) Rules, 2017 issued vide Notification No. 55/2017-NT-Customs dated 21.06.2017 prescribes that Director General may proceed expeditiously with the conduct of the investigation and in critical circumstances, Director General may record a preliminary finding regarding increased imports causing serious injury or threat of serious injury to the domestic industry and where delay in imposition of provisional bilateral safeguard measure would cause damage which would be difficult to repair. The principles governing investigations have been provided in the Rule 5 of the India-Malaysia Comprehensive Economic Cooperation Agreement (Bilateral Safeguard Measures) Rules, 2017, which is independent to Rule 8. Rule 13 provides for refund of differential Safeguard duty in case safeguard duty imposed after conclusions of the investigations is lower than the provisional duty already imposed and collected. The harmonious reading of Rules 5, 8 and 13 of the said Rules leads to a conclusion that the Rules provide for expeditious recommendation of provisional Safeguard duty based on preliminary findings, and refund of the differential duty in case it is ascertained that the duty imposed after conclusion of investigation (final findings) as enshrined in the Rule 5 is lower than the provisional Safeguard Duty. However, in critical circumstances, any delay in imposition of Provisional Safeguard duty may cause damage which would be difficult to repair. Accordingly, it was considered prudent to analyze circumstances to assess whether the same falls in the category of critical circumstances.
7. It is noted that subject imports have increased very significantly from 626,362 Mt in 2016-17 to 1,974,337 MT (on annualised basis) in Jan.-March, 2019 and further to 3,218,112 MT (on annualised basis) in April-June, 2019 period which is 87 % of total imports in India, 112% of Indian production and 40% Indian consumption. The petitioners have claimed that the steep increase in subject imports has led to critically significant adverse impact on the domestic producers and utilisation of their production facilities for the product. They have also claimed in their petition that considering significant surge in subject imports and further threat of increase in imports, serious injury to the domestic producers is imminent in case immediate safeguard measures are not invoked in accordance with the said rules. The Director General therefore has examined the contention of the petitioners if there exists a critical situation warranting imposition of provisional safeguard measures, and whether any delay in the imposition of provisional measures would cause damage, which would be difficult to repair.

8. A careful reading of various provisions of the said rules and the Agreement shows that the rules contemplate recording of interim measures in appropriate cases without waiting for questionnaire response and other information from the interested parties. It would therefore be appropriate to examine request for imposition of bilateral safeguard measures without waiting for the replies to the notice of initiation. However, the Director General shall consider any information/evidence or justification given by any interested party during the process of investigation on all aspects of investigations.

C. Examination of the petition:

9. The application filed by the petitioner has been examined for immediate imposition of safeguard duty. Accordingly, the information made available by the petitioner in their petition and subsequent submissions, have been considered by the Director General for the purpose of the preliminary determination. The Director General shall however record its final determination, after receipt of information and views from all interested parties.

I. The product under Consideration (PUC)

10. The product under consideration in the present investigation is “Refined Bleached Deodorised Palm Oil” and “Refined Bleached Deodorised Palmolein” (also known as RBD Palm Oil and RBD palmolein, respectively), falling under the HS code 15119010 and 15119020 of the Customs Tariff Act. RBD Palmolein is refined, bleached and deodorized form of palm oil which is extracted after crushing palm fruit. Product under consideration is commonly used to formulate trans-free fats such as margarine, shortening and vegetable ghee.

II. Domestic Industry

11. Rule 2 (b) of the India-Malaysia Comprehensive Economic Cooperation Agreement (Bilateral Safeguard Measures) Rules, 2017 provides as follows:

*“domestic industry” means, with respect to an imported good, the producers -
(i) as a whole of the like good or directly competitive good in India; or*

12. Further, Rule 4 provides as follows with regard to filing of application:

The Director General shall, on receipt of a written application by or on behalf of the domestic producer of like good or directly competitive good, initiate an investigation to determine the existence of serious injury or threat of serious injury to the domestic industry, caused by increased imports of an originating good as result of the reduction or elimination of a customs duty under the Trade Agreement

13. The application has been filed by the Solvent Extractors’ Association of India on behalf the domestic producers of “Refined Bleached Deodorised Palm Oil” and “Refined Bleached Deodorised Palmolein” in India. The petition contains information for the Indian industry as a whole. The following domestic producers have specifically sought imposition of bilateral safeguard measures.

- a. 3F Industries Ltd.,
- b. Adani Wilmar Ltd.,
- c. COFCO International,
- d. Emami Agrotech Ltd,
- e. Gemini Edible Fats & Oils Ltd.
- f. Gokul Agro Resources Ltd,
- g. Liberty Oil Mills Ltd.,
- h. Ozone Procon Pvt. Ltd.,
- i. Ruchi Soya Industries Ltd. (6 Units),

14. It is considered that the petition has been filed on behalf of the “domestic producers as a whole” of the like article in India, and Solvent Extractors’ Association of India has been taken as domestic industry for the purpose of this investigation.

III. Period of Investigation (POI)

15. The period January-June, 2019 has been considered as the investigation period (POI) for the purpose of a determination of whether imports of the RBD have increased in such quantity so as to constitute “increased imports”. The applicable customs duties on Crude Palm Oil and subject goods changed with effect from 1st January, 2019. Neither the domestic laws nor Agreement on Safeguards and Article XIX of GATT nor India and India-Malaysia Comprehensive Economic Cooperation Agreement (Bilateral Safeguard Measures) Rules, 2017 provide any specific guidelines on the period of investigation except the fact that the relevant investigation period should be sufficiently long to allow conclusion to be drawn on increased import and serious injury or threat of serious injury to the Indian industry. The injury investigation period has been considered as the period 2016-17, 2017-18, Apr.-Dec., 2018 and the POI. The figures in the present findings for the periods Apr.-Dec., 2018 and POI have been mentioned on annualised basis in order to make them comparable to the previous year period.

IV. Source of Information

16. Since the subject goods have dedicated customs code, import data for the period from April 2015 to June 2019 have been considered as per import-export data published by DGCIS. Information with regard to serious injury has been considered for the domestic producers as a whole as furnished by Solvent Extractors’ Association of India.
17. Information with regard to serious injury has been provided by the petitioners in respect of domestic producers as a whole. After initiation, the Director General issued questionnaire to the Solvent Extractors’ Association of India and also individual producers as per list made available by the association directing them to provide information as per prescribed questionnaire. The said information has been provided by following domestic producers.
- a. Emami Agrotech Ltd
 - b. Liberty Oil Mills Ltd.
 - c. Gemini Edible Fats & Oils Ltd
 - d. Adani Wilmar Ltd.
 - e. Gokul Agro Resources Ltd
 - f. Vimal Oil & Foods Ltd
 - g. Ozone Procon Pvt Ltd
18. The Director General has considered evaluation of injury and serious injury on the following basis.
- a. Parameters such as market share, capacity, production, domestic sale, capacity utilisation, sales have been determined first for domestic producers as a whole and thereafter also for the participating companies.
 - b. Parameters such as profit, wages, and employment have been examined in respect of all domestic producers on a consolidated basis. These parameters have also been analysed on individual basis with respect to responding domestic producers.
19. For threat of serious injury, the Director General has considered information as made available by the petitioner in their application, and additional information filed post initiation. A copy of the information filed by the petitioner post initiation of investigation has been placed in public file for perusal of the parties to allow them to offer their comments if any, which shall be considered for final determination.

V. Increased imports from subject country

20. India – Malaysia CECA (Agreement) and India-ASEAN AIFTA (Agreement) provided reduction of customs duty on CPO and RBD as mentioned below.

MICECA Preferential Tarrifs			
	Tarrif line	CPO	RPO

	Base Rate	80	90
	EIF*	72	82
Not Later than	1.1.2012	68	78
	1.1.2013	64	74
	1.1.2014	60	70
	1.1.2015	56	66
	1.1.2016	52	62
	1.1.2017	48	58
	1.1.2018	44	54
	31.12.2018	40	45

	AIFTA Preferential Tariffs		
	Tariff line	CPO	RPO
	Base Rate	80	90
Not Later than	2010	76	86
	2011	72	82
	2012	68	78
	2013	64	74
	2014	60	70
	2015	56	66
	2016	52	62
	2017	48	58
	2018	44	54
	2019	40	50

21. It is noted that the customs duty differential between Crude Palmolein oil (CPO) and subject goods i.e Refined Bleached Deodorised Palm Oil” (RBD Palm oil) and “Refined Bleached Deodorised Palmolein (RBD Palmolein) was 10 % during the period from April, 2015 till Dec., 2018. The customs duty differential however reduced to 5% w.e.f. 01.01.2019. This reduction in customs duty differential has resulted in significant increase in subject imports from Malaysia with consequent decline in imports of crude palm oil.

VI. Increased Imports from Malaysia

22. Rule 2 (d) of India-Malaysia Comprehensive Economic Cooperation Agreement (Bilateral Safeguard Measures) Rules, 2017 provides as follows:

“increased imports” means increase in imports from Malaysia whether in absolute terms or relative to domestic production

23. The said rules require an examination whether imports of the PUC increased in such quantities in absolute and relative terms so as to constitute “increased imports”. The said rules require an analysis of the imports, in both absolute terms and in relation to imports into India, production and consumption in India. Analysis of increased imports of the product under consideration has been conducted having regard to the said rules.

i. Imports from Malaysia in absolute terms:

24. The movement of imports is shown in the table below:

SN	Period	Volume (MT)		
		Malaysia	Other countries	Total imports
1	2016-17	626,362	2,315,292	29,41,654

2	2017-18	376,136	2,308,482	26,84,618
3	2018-19	696,909	1,729,644	24,26,553
4	Apr.-Dec.2018 (Annualised)	271,099	1,986,498	22,57,597
5	POI (Annualised)	2,596,225	725,210	33,21,435
Imports on quarterly basis (MT)				
1	Q1 18-19	97,239	470,534	5,67,773
2	Q2 18-19	78,879	640,816	7,19,695
3	Q3 18-19	27,206	378,524	4,05,730
4	Q4 18-19	493,584	239,771	7,33,355
5	Q1 19-20	804,528	122,834	9,27,362

25. The imports of the product under consideration have increased significantly in the POI in absolute terms. There is a sharp and significant increase in imports of PUC during the POI. Imports from Malaysia increased from 626,362 MT in 2016-17 to 2,596,225 MT in Jan-June, 2019 (on annualized basis) thus showing an increase of 314%. Imports from other countries declined from 2,315,292 MT in 2016-17 to 7,25,210 MT in Jan-June, 2019 (on annualized basis).
26. Analysis of quarterly movement in imports shows that imports were 27,206 MT in Oct.-Dec., 2018, which surged to 804,528 MT in Apr.-June, 2019 thus showing a surge of almost 29 times.

ii. Share of increase in imports of subject goods from Malaysia and other countries

27. The share of imports of subject goods from Malaysia and other countries is shown in the table below:

SN	Period	Share in Imports (%)	
		Malaysia	Other countries
1	2016-17	21%	79%
2	2017-18	14%	86%
3	2018-2019	29%	71%
4	Apr.-Dec.2018	12%	88%
5	POI annualized	78%	22%
Imports on quarterly basis			
1	Q1 18-19	17%	83%
2	Q2 18-19	11%	89%
3	Q3 18-19	7%	93%
4	Q4 18-19	67%	33%
5	Q1 19-20	87%	13%

28. It is noted that imports of the product under consideration from Malaysia in 2016-17 was 21% of total imports into India. The volume of imports did not rise till Dec., 2018 in relation to total imports of the product under consideration in India. However, the share of imports from Malaysia increased significantly during POI. The imports of subject goods from Malaysia increased significantly by 78% during the POI. Overall share of imports of product under consideration from Malaysia have increased to almost 4 times in the POI as compared to the base year.

iii. Increase in imports in relation to production and consumption in India

29. The movement of imports of subject goods in relation to production and consumption in India is shown in the table below:

SN	Period	Imports Malaysia	Indian Production	Indian Consumption	Imports in relation to (%)	
		MT	MT	MT	Production	Consumption
1	2016-17	626,362	4,247,839	7,190,365	15%	9%
2	2017-18	376,136	5,308,775	7,995,216	7%	5%

3	2018-19	696,909	5,070,583	7,510,304	14%	9%
4	Apr.-Dec., 2018 (annualized)	271,099	4,965,180	7,237,288	5%	4%
5	POI (annualized)	2,596,225	4,847,732	8,174,382	54%	32%
6	Q1 18-19	97,239	952,452	1,527,291	10%	6%
7	Q2 18-19	78,879	1,269,789	1,990,599	6%	4%
8	Q3 18-19	27,206	1,501,645	1,910,075	2%	1%
9	Q4 18-19	493,584	1,346,697	2,082,338	37%	24%
10	Q1 19-20	804,528	1,077,169	2,004,852	75%	40%

30. It is noted that imports of subject goods from Malaysia constituted 15% and 9% respectively of the production and consumption in India in 2016-17. The share of Malaysia, however, surged to 54% and 32% respectively during the POI. Thus, imports have shown significant increase in imports in relation to production and consumption. The increase in imports in relation to production and consumption is considered significant in such a short period.

VII. Serious Injury

31. Serious Injury and Threat of serious injury is defined as follows under the Rules:

(c) serious injury means a significant overall impairment in the position of a domestic industry; and

(d) threat of serious injury means serious injury that is clearly imminent and shall be determined on the basis of facts and not merely on allegation, conjecture or remote possibility.

32. Thus, increase in imports should be such which causes a significant overall impairment in the position of a domestic industry

33. Rule 7 of the Rules further provides as follows:

The Director General shall determine serious injury or threat of serious injury to the domestic industry taking into account, inter alia, the following principles, namely :-

(a) the Director General shall evaluate all relevant factors of an objective and quantifiable nature having a bearing on the situation of that domestic industry, in particular, the rate and amount of the increase in imports of the originating good in absolute and relative terms, the share of the domestic market taken by increased imports of the originating good, changes in the level of sales, production, productivity, capacity utilisation, profits and losses and employment;

34. It is noted that evaluation of the listed parameters needs to take into account peculiarities of different industries and situations. The Director General has therefore examined serious injury to the domestic industry, having regard to the facts of the present case and the situation of the industry. Thus, in addition to a technical examination of all the listed factors and any other relevant factors, it is essential that the overall *position* of the industry is evaluated, in light of all the relevant factors having a bearing on the situation of that industry. Accordingly, in analyzing serious injury and threat of serious injury, all factors, which are mentioned in the rules as well as other factors which are relevant for determination of serious injury or threat of serious injury, have been considered. The determination of serious injury or threat of serious injury is based on evaluation of the overall position of the industry, in light of all the relevant factors having a bearing on the situation of that industry.

35. Rule 3 (b) states as follows

the Director General shall evaluate all relevant factors of an objective and quantifiable nature having a bearing on the situation of that domestic industry, in particular, the rate and amount of the increase in imports of the originating good in absolute and relative terms, the share of the domestic market taken by increased imports of the originating good, changes in the level of sales, production, productivity, capacity utilisation, profits and losses and employment;

36. The serious injury and threat of serious injury to the domestic industry on account of increased imports of subject goods has been examined by evaluating the following factors as listed under the rules:

a. Increase in imports in absolute and relative terms

37. It is noted that the imports of subject goods have increased significantly in absolute as well as in relative terms in the recent period. The increase in imports is both in absolute terms as well as in relation to total imports, Indian production and consumption. Further, the increase in imports is noted when the situation is compared between 2016-17 and Jan.-June, 2019, or with the period immediately preceding the surge period. It is also noted that there was significant increase in imports in April-June, 2019 as compared to preceding quarter.

b. Production and Sales:

38. The Petitioner has submitted that the only source of production is either domestic or imported raw material and the only use of raw material is in production of the product under consideration. They have also claimed that the producers cannot hold either raw material inventories or finished product inventories for long period due to low shelf life of the product at every stage from the stage of plucking of flower to consumption of oil. It was also the contention of the petitioner that the consumption norms for production of product from the raw material are not only fairly standardized but they can also be considered globally the same. The Petitioner has also submitted relevant material from the Round Table on Sustainable Palm Oil evidencing therein the input output ratio between CPO and RBD oil. The petitioner has also submitted that sales can be considered at the same level as production as the product cannot be kept in stocks for long.

39. In view of the above, gross Indian production and domestic sales have been assessed considering such consumption norms. For the purpose, consumption of raw material (CPO) has been considered on the basis of imports of CPO in India, as publicly reported by the DGCI&S.

40. The domestic production and sales following the above stated methodology is as follows:

SN	Period	Production/Sales	Demand
		MT	MT
1	2016-17	4,247,839	7,190,365
2	2017-18	5,308,775	7,995,216
3	2018-19	5,070,583	7,510,304
4	Apr-Dec'18 annualized.	4,965,180	7,237,288
5	POI annualized	4,847,732	8,174,382

41. It is noted that the demand of the subject goods was declining since the base year and the domestic production and sales have also shown corresponding decline. The demand, however, increased during the POI and has gone back to the level prevailing in the base year, whereas, the Indian production and sales have further declined. In other words, whereas demand increased in POI, production and sales of the domestic producers increased. The decline in production/sales becomes evident on comparison of the period April-Dec 2018 with that of POI (Jan-June 2019). The Indian production/sales was 4,965,180MT in April-Dec 2018 which declined to 4,847,732 MT in the POI, i.e., a decline of more than 2.4%.

c. Capacity utilization

42. The details of capacity and capacity utilisation are as follows:

Period	Capacity (MT)	Capacity utilisation	Production Volume (MT)
2016- 17	1,39,00,000	31%	42,47,839
2017-18	1,39,00,000	38%	53,08,775

2018-19	1,39,00,000	36%	50,70,583
2019-20 (Q1)	1,39,00,000	21%	28,82,534
Q1 17-18	34,75,000	34%	11,80,275
Q2 17-18	34,75,000	40%	13,76,532
Q3 17-18	34,75,000	39%	13,50,830
Q4 17-18	34,75,000	40%	14,01,139
Q1 18-19	34,75,000	27%	9,52,452
Q2 18-19	34,75,000	37%	12,69,789
Q3 18-19	34,75,000	43%	15,01,645
Q4 18-19	34,75,000	39%	13,46,697
Q1 19-20	34,75,000	31%	10,77,169
Apr-Dec'18	1,04,25,000	36%	37,23,885
POI Jan-June'19	69,50,000	35%	24,23,866

43. It is noted that domestic industry has significant underutilised capacity and their capacity utilisation has gone down during the POI.

d. Market share of the domestic industry

44. The movement of market share is as follows:

SN	Period	Market Share (%)	
		Malaysia	Indian industry
2	2016-17	9%	59%
3	2017-18	5%	66%
4	2018-19	9%	68%
5	Apr-Dec'18	4%	69%
6	POI	32%	59%
7	Jan.-March, 2019	24%	65%
8	Apr-June, 2019	40%	54%

45. It is noted that market share of domestic industry has declined whereas market share of imports of subject goods from Malaysia have increased during the POI as compared to earlier years.

e. Employment and Productivity

46. The petitioner has claimed that manhours deployed in processing of product under consideration has declined significantly in the current period and considering annual loss of production/sales to the extent of 11.59 lacs (considering sales in Oct-Dec 2018 and POI), the employment deployed for the product has declined by about 3,000. Given the fact that there is a decline in production of subject goods, the productivity has declined.

f. Profit/loss

47. The net value of subject goods and the target price including reasonable return from imported crude Palm oil is as follows:

Crude Import	Unit	POI Ann.
Volume (MT)	MT	***
Import value Rs. Laks	Rs.laks	***

CIF Rate Rs./MT	Rs./MT	***
Customs duty %	%	***
Customs duty amount	Rs./MT	***
Cess amount	Rs./MT	***
Landed cost	Rs./MT	***
Consumption factor		***
RM cost		***
Less: By product	Rs./MT	***
Conversion Cost	Rs./MT	***
Net value of Palm Oil	Rs./MT	***
Reasonable return	5%	***
Target price	Rs./MT	***

48. As against the above target price, the landed price of imported RBD Palmolein from Malaysia is as follows:

Volume (MT)	MT	2,596,225
CIF rate	Rs./MT	40,997
Customs duty	%	45%
Customs duty amount	Rs./MT	18,449
Cess amount	Rs./MT	553
Landed price of RBD Palmolein	Rs./MT	60,000

49. It has been claimed that if the domestic producers match the price of the imported subject goods, the producers will not be able to recover even their costs and would suffer significant losses. In fact, it is noted that the domestic producers themselves started importing RBD oil in order to remain in the market. Resultantly, the domestic producers have lost significant production and resultant sales. This has resulted in significant loss of profits to the domestic producers. Considering the reasonable profit of Rs *** PMT, the estimated profitability of the domestic industry declined significantly over the period, as is noted from the following:

	Sales	Profits
	MT	Rs. Crs
2016- 17	42,47,839	***
2017-18	53,08,775	***
Q1 18-19	9,52,452	***
Q2 18-19	12,69,789	***
Q3 18-19	15,01,645	***
Q4 18-19	13,46,697	***
Q1 19-20	10,77,169	***

50. It is noted that estimated profits of the domestic industry declined significantly during the POI.

g. Price suppression/depression and Price undercutting:

51. Comparison of landed price of subject goods with that of the reasonable price derived for the subject goods is shown in the table below:

Particulars	Unit	Amount
Reasonable price of RBD Palm Oelin	Rs./MT	***
Landed price of RBD Palmolein	Rs./MT	***
Difference	Rs./MT	***

52. It is noted that landed price of RBD Palmolein is significantly below the level of reasonable price of RBD Palm olein required by the domestic producers, should they import CPO and process the same into subject goods. This shows that the imports are suppressing the prices of the domestic producers to such an extent that the domestic producers are not even undertaking production activities to that extent. The difference between landed price of imports and reasonable price is significant indicating significant price undercutting by the imports of Malaysia.

Injury analysis of Domestic producers who have provided data

53. In addition to the analysis of performance of the industry in respect of domestic producers as a whole, the Director General has analysed performance of those companies who provided information post initiation. Following domestic producers have provided information pertaining to capacity, production, sales, employment, wages, productivity and profits.
- Emami Agrotech Ltd
 - Liberty Oil Mills Ltd.
 - Gemini Edible Fats & Oils Ltd
 - Adani Wilmar Ltd.
 - Gokul Agro Resources Ltd
 - Vimal Oil & Foods Ltd
 - Ozone Procon Pvt Ltd
54. It is noted from the petition and subsequent submissions that production and sales of these companies were increasing till Dec., 2018. The production and sales however declined by 23% (POI) and 31% (April-June, 2019). The decline in production and sales is considered significant. Consequently, the capacity utilisation and profits of these companies have also declined significantly. Employment and wages have largely remained the same. Productivity however declined significantly.
55. The performance of individual companies was also examined over the same period. It is noted that production, productivity and sales of most of these companies were increasing till Dec., 2018 and declined significantly during the POI

	Production (Quarterly) in MT						
	Gemini	Ozone	Gokul	Emami	Adani	Liberty	Vimal
2016- 17	***	***	***	***	***	***	***
2017-18	***	***	***	***	***	***	***
Q1 18-19	***	***	***	***	***	***	***
Q2 18-19	***	***	***	***	***	***	***
Q3 18-19	***	***	***	***	***	***	***
Q4 18-19	***	***	***	***	***	***	***
Q1 19-20	***	***	***	***	***	***	***

	Capacity Utilisation						
	Gemini	Ozone	Gokul	Emami	Adani	Liberty	Vimal
2016- 17	***	***	***	***	***	***	***
2017-18	***	***	***	***	***	***	***
Q1 18-19	***	***	***	***	***	***	***
Q2 18-19	***	***	***	***	***	***	***
Q3 18-19	***	***	***	***	***	***	***
Q4 18-19	***	***	***	***	***	***	***
Q1 19-20	***	***	***	***	***	***	***

	Productivity Per Day in MT						
	Gemini	Ozone	Gokul	Emami	Adani	Liberty	Vimal
2016- 17	***	***	***	***	***	***	***
2017-18	***	***	***	***	***	***	***
Q1 18-19	***	***	***	***	***	***	***
Q2 18-19	***	***	***	***	***	***	***
Q3 18-19	***	***	***	***	***	***	***
Q4 18-19	***	***	***	***	***	***	***
Q1 19-20	***	***	***	***	***	***	***

	Production (Indexed)						
	Gemini	Ozone	Gokul	Emami	Adani	Liberty	Vimal
2016- 17	100	100	100	100	100	100	100
2017-18	193	1,747	145	124	111	173	40
Q1 18-19	351	1,949	58	86	94	50	-
Q2 18-19	301	2,159	86	117	105	46	-
Q3 18-19	415	2,869	201	149	150	145	-
Q4 18-19	368	2,360	91	131	124	202	-
Q1 19-20	330	762	66	116	87	212	-

	Capacity Utilisation (Indexed)						
	Gemini	Ozone	Gokul	Emami	Adani	Liberty	Vimal
2016- 17	100	100	100	100	100	100	100
2017-18	193	1,747	145	124	111	173	40
Q1 18-19	351	1,949	58	86	94	50	-
Q2 18-19	301	2,159	86	117	105	46	-
Q3 18-19	415	2,869	201	149	150	145	-
Q4 18-19	368	2,360	91	131	124	202	-
Q1 19-20	330	762	66	116	87	212	-
	Productivity Per Day (Indexed)						
	Gemini	Ozone	Gokul	Emami	Adani	Liberty	Vimal
2016- 17	100	100	100	100	100	100	100
2017-18	193	1,747	145	124	111	173	40
Q1 18-19	351	1,949	58	86	94	50	-
Q2 18-19	301	2,159	86	117	105	46	-
Q3 18-19	415	2,869	201	149	150	145	-
Q4 18-19	368	2,360	91	131	124	202	-
Q1 19-20	330	762	66	116	87	212	-

Conclusion

56. From the above analysis, it is thus provisionally concluded that the imports of the product under consideration have increased significantly in absolute terms and in relation to gross imports in India, Indian production and consumption. As a result of significant surge in imports from Malaysia, the domestic producers have suffered serious injury in terms of significant decline in production, sales, capacity utilization, market share, profits out of refining operations and manpower deployed for processing the product. Considering the performance of the domestic producers in respect of various parameters, it is provisionally concluded, pending further investigations, including verifications, that the domestic industry has suffered serious injury as a result of increased imports of the product under consideration from Malaysia.

VIII. Threat of Serious Injury

57. The Rules provides as follows:

“threat of serious injury” means serious injury that is clearly imminent and shall be determined on the basis of facts and not merely on allegation, conjecture or remote possibility;

58. The Panel on US — Lamb considered that a focus on the recent data available pertaining to the end of an investigation period was logical in view of the future-oriented nature of a threat of serious injury analysis. The relevant extracts are as follows:

“In our view, due to the future-oriented nature of a threat analysis, it would seem logical that occurrences at the beginning of an investigation period are less relevant than those at the end of that period. While the SG Agreement does not specify the appropriate duration of the time-period to be considered in an investigation, the Panel and Appellate Body in Argentina — Footwear both considered this issue to some extent. Both concluded that (for an actual serious injury finding) the most recent data were clearly the most relevant. In particular, the Appellate Body stated that ‘the relevant investigation period should not only end in the very recent past, the investigation period should be the recent past’.

Given that a threat of serious injury pertains to imminent significant overall impairment, i.e., an event to take place in the immediate future, the same principle should hold true a fortiori for threat determinations compared with present serious injury determinations. This supports the view that the USITC was correct to focus on the most recent data available from the end of the investigation period. We also consider that data from 1997 and interim-1998 cover an adequate and reasonable time-period if complemented by projections extrapolating existing trends into the imminent future so as to ensure the prospective analysis which a threat determination requires.

Therefore, we consider that, by basing its determination on events at the end of the investigation period (i.e., one year and nine months) rather than over the course of the entire investigation period, the USITC analyzed sufficiently recent data for making a valid evaluation of whether significant overall impairment was “imminent” in the near future. By the same token, we also consider that, by basing its determination at all on data about events from the recent past, rather than relying exclusively on projections for the various industry indicators into the future, the USITC made its threat determination on the basis of objective and quantifiable facts, and ‘not merely on allegation, conjecture or remote possibility’

59. The Panel Report on US — Lamb, in a finding subsequently not reviewed by the Appellate Body, which addressed the question whether once imports have increased to already cause some degree of injury, there is no requirement of additional increased imports in order to legitimately determine the existence of a threat of serious injury. The relevant extracts are as follows:

“The complainants further claim that the US reference to projections of future increases in imports in defending its threat analysis amounts to equating a ‘threat of increased imports’ with a ‘threat of serious injury’, which the Argentina — Footwear panel found not to be permissible....

We agree in general with the complainants’ argument that a threat of increased imports as such cannot be equated with threat of serious injury. However, in our view, this is not what the USITC has done in this case. Moreover, we also deem it possible that imports continuing on an elevated level for a longer period without further increasing at the end of the investigation period may, if unchecked, go on to cause serious injury (i.e., may threaten to cause serious injury). That is, if increased imports at a certain point in time cause less than serious injury, it is not necessarily true that a threat of serious injury can only be caused by a further increase, i.e., additional increased imports. In our view, in the particular circumstances of a case, a continuation of imports at an already recently increased level may suffice to cause such threat.

60. It is noted that imports of subject goods from Malaysia are entering the Indian market in significant increased quantities in absolute terms as well as in relation to production and consumption in India. The domestic industry’s capacity was underutilized and the intensified imports from Malaysia has adversely impacted the situation. Considering the difference between the landed price of imports of subject goods and the reasonable price of subject goods, the huge capacities with Malaysia coupled with the fact of their high export orientation shows that the subject goods from Malaysia is likely to remain lucrative, posing continued threat of injury to the domestic industry. The threat of serious injury is established by the following factors:-

- a. The price difference between the domestic and imported product has led to increase in imports of subject goods from Malaysia.
 - b. The producers from Malaysia are holding significant unutilized capacities. Resultantly, producers and exporters from Malaysia are continuously looking for additional markets to the extent possible.
 - c. The demand of the product is growing and the Indian market is large and price sensitive.
 - d. As there is significant difference between the cost of sales of the domestic producers out of imported CPO and import price of RBD oil, the domestic producers curtailed refining activities and turned to imports of CPO.
61. In view of above it is provisionally concluded that the increased imports of subject goods from Malaysia have caused serious injury to the domestic industry. Further, the domestic industry is faced with continued threat of serious injury from imports from Malaysia.

IX. Causal Link

62. A comprehensive evaluation of parameters enumerated above demonstrates that serious injury and threat of serious injury is being caused by increased imports. For the purpose of determining causation, all relevant factors of an objective and quantifiable nature having a bearing on the situation of the industry have been evaluated. In the instant case, the following are relevant in this regard —
- a. The imports of PUC have increased significantly in the POI in absolute as well as relative terms.
 - b. The market share of domestic producers have declined whereas that of imports from Malaysia has increased.
 - c. The landed price of import is significantly lower than the reasonable price of subject goods.
 - d. Domestic producers are forced to import goods in order to maintain its market presence.
 - e. Sales and consequently production, capacity utilisation, manpower deployed and profits of the domestic producers have declined as a result of increased imports.
63. It is thus evident that injury to the domestic industry has been caused by the increased imports and there is a causal link between increased imports of subject goods from Malaysia and serious injury and threat of serious injury to the domestic industry.

X. Critical Circumstance

64. Rule 8 prescribes that, the Director General shall proceed expeditiously with the conduct of the investigation and in critical circumstances, where there is clear evidence that increased imports have caused or are threatening to cause serious injury to the domestic industry and where delay in imposition of provisional bilateral safeguard measure would cause damage which would be difficult to repair, may record a preliminary findings regarding serious injury or threat of serious injury to the domestic industry as a result of increased imports of an originating good. Since the petitioner requested immediate imposition of safeguard measures, the request of the petitioner was examined in the light of the legal requirements and facts of the case. It is noted that
- a. The import of PUC into India has shown significant increase. Imports of subject goods from Malaysia increased from 626,362 MT in 2016-17 to 2,596,225 MT in Jan-June, 2019 (on annualized basis) thus showing an increase of 314%.
 - b. Quarterly movement in imports shows that imports were just 27,206 MT in Oct.-Dec., 2018, which surged to 804528 MT in Apr-June, 2019 thus showing a surge of almost 29 times increase.
 - c. This increase in import at low prices has led to idling of significant capacities of the domestic industry during the period of investigation. Though domestic industry has huge installed capacity, it is unable to increase its production of subject goods despite increase in domestic demand of the PUC.
 - d. Market share of the domestic industry has declined significantly.
65. It is noted that these are the factors which constitute critical circumstances in the instant case that have affected the overall performance of the Indian industry and have caused serious injury and threat of further serious injury to the domestic producers. It is therefore considered appropriate to arrest the surge in imports in order to prevent further injury to the domestic industry.

XI. Conclusion and recommendation:

66. On the basis of the preliminary findings above, it is provisionally concluded that increased imports of PUC have caused serious injury and are threatening to cause serious injury to domestic producers. As a result, production/sales of the domestic producers declined significantly resulting into decline in capacity utilisation in the POI. The domestic industry has been forced to import subject goods to maintain their presence in the market. Imports at lower prices are adversely affecting the prices of the domestic industry. Thus, it is considered that critical circumstances exist where delay in imposition of safeguard measures would cause irreparable damage to the domestic producers. With regard to imposition of bilateral safeguard measure, Rule 9 of the India-Malaysia Comprehensive Economic Cooperation Agreement (Bilateral Safeguard Measures) Rules, 2017 state as follows:

9. Application of provisional bilateral safeguard measure.- (1) *The Central Government, on the basis of the preliminary findings of the Director General, may -*

- (a) *suspend further reduction of any rate of customs duty on the originating good provided for under the Trade Agreement from the day when the bilateral safeguard measure is taken; or*
- (b) *Increase the rate of customs duty on the originating good to a level not to exceed the lesser of:*
 - (i) *the Most Favoured Nation applied rate of custom duty on the originating good in effect on the day when the bilateral safeguard measure is taken; or*
 - (ii) *the Most Favoured Nation applied rate of custom duty on the originating good in effect on the day immediately preceding the date of the start of the period of investigation.*
- (2) *The bilateral safeguard measure under sub-rule (1) shall remain in force only for a period not exceeding two hundred days from the date of its imposition.*

67. After examining the above, it is considered appropriate to impose Provisional bilateral Safeguard measure in terms of Rule 9 of India-Malaysia Comprehensive Economic Cooperation Agreement (Bilateral Safeguard Measures) Rules, 2017. Accordingly, the Director General recommends increase in rate of customs duty on imports of subject goods originating in Malaysia by 5%, for a period of 180 days which is considered appropriate to safeguard the interest of domestic industry.

XII. Further Process:

68. The following further procedure would be followed subsequent to notifying the preliminary findings:
- i. The Director General invites comments on preliminary findings from all known interested parties within 21 days from the date of issue of preliminary findings. The comments received from them would be examined in the final findings.
 - ii. The Director General would conduct oral hearing to give an opportunity to all interested parties to present their views relevant to the investigation. Issues and concerns raised during oral hearing will be examined in the final findings.
 - iii. The date of the oral hearing would be announced on the DGTR website (dgtr.gov.in).
 - iv. The Director General would conduct verification to the extent deemed necessary.

SUNIL KUMAR, Addl. Secy. and Director General